छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज की गृह पत्रिका

संकल्प

जून 2025 | वर्ष 22 | अंक 03

केन्द्र व राज्य की योजनाओं से आदिवासी अंचलों में हर घर बिजली पहुंचाने की मुहिम तेज

मोदी की गारन्टी- विष्णु का सुशासन



विद्युत विकास के बढ़ते कदम

विवरण	नवम्बर 2000	मई 2025
ताप विद्युत क्षमता	1,240 मेगावॉट	2,840 मेगावॉट
जल विद्युत क्षमता	120 मेगावॉट	138.70 मेगावॉट
कुल ताप, जल विद्युत क्षमता	1,360 मेगावॉट	2,978 मेगावॉट
अति उच्चदाब उपकेन्द्रों की संख्या	27 नग	135 नग
अति उच्चदाब लाइनों की लंबाई	5,205 सर्किट किमी	14,350 सर्किट किमी
400 केवी उपकेन्द्र की संख्या	1 नग	4 नग
400 केवी उपकेन्द्र की क्षमता	945 एमवीए	3,465 एमवीए
400 केवी लाइन की लंबाई	277 किमी	1,932 किमी
220 केवी उपकेन्द्र की संख्या	5 नग	28 नग
220 केवी उपकेन्द्र की क्षमता	1,350 एमवीए	10,960 एमवीए
220 केवी लाइन की लंबाई	1594.30 किमी	4,269 किमी
132 केवी उपकेंद्र की संख्या	20 नग	103 नग
132 केवी उपकेंद्र की क्षमता	1,257 एमवीए	12,050 एमवीए
132 केवी लाइन की लंबाई	2,974 किमी	8,311 किमी
33/11 केवी उपकेन्द्र की संख्या	248 नग	1,468 नग
33/11 केवी उपकेन्द्रों की क्षमता	1,033 एमवीए	10,081 एमवीए
33 केवी लाइन की लंबाई	6,988 सर्किट किमी	25,848 सर्किट किमी
11/04 केवी उपकेन्द्र की संख्या	29,692 नग	2,48,718 नग
11/04 केवी उपकेन्द्र की क्षमता	1,951 एमवीए	1,44,91 एमवीए
11 केवी लाइन की लंबाई	40,556 किमी	1,44,843 किमी
निम्नदाब लाइन की लंबाई	51,314 किमी	2,43,215 किमी
उपभोक्ताओं की संख्या निम्नदाब	18,90,998	65,00,645
उपभोक्ताओं की संख्या उच्चदाब	530	4,151
विद्युतीकृत पंपों की संख्या (प्रावधिक)	73,369	5,87,922
अस्थायी पंपों की संख्या	–	2,52070
ग्रामीण विद्युतीकरण संख्या	17,108	19,609
अधिकतम मांग	1,334 मेगावॉट	7003 मेगावॉट

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज की गृह पत्रिका

संकल्प

जून 2025 | वर्ष - 22 | अंक-3

संरक्षक



श्री सुबोध कुमार सिंह IAS
माननीय अध्यक्ष
सीएसपीटीसीएल



डॉ.रोहित यादव IAS
माननीय अध्यक्ष
सीएसपीजीसीएल / सीएसपीडीसीएल



श्री एस.के. कटियार
प्रबंध निदेशक
सीएसपीजीसीएल



श्री आर.के. शुक्ला
प्रबंध निदेशक
सीएसपीटीसीएल



श्री भीम सिंह कंवर
प्रबंध निदेशक
सीएसपीडीसीएल

संपादक



उमेश कुमार मिश्र
अति. महाप्रबंधक, जनसंपर्क

संपादन सहयोग - गोविन्द पटेल, अनामिका मण्डावी

छाया : संजय टेम्भे

कार्यालय सहयोग : प्रसन्न कुमार दुबे, शुभम बंछोर

फोन : 0771-2574702, 98936-24511

E-mail : procsphcl@gmail.com, powercomu01@gmail.com

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के लिए, कार्यालय अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) द्वारा प्रकाशित। प्रमाणित किया जाता है कि पत्रिका के अंदर के पृष्ठों में 90 जीएसएम आर्ट पेपर (सिनारमास) और कवर पृष्ठों में 250 जीएसएम आर्ट पेपर (सिनारमास) का उपयोग किया गया है- मुद्रक : मयंक ऑफसेट प्रिंटर्स, रायपुर

क्रम





पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में डबल सब्सिडी की सौगात	02
आदिवासी अंचलों और घरों में बिजली पहुंचाने की मुहिम तेज	04
बस्तर पहुंचे ऊर्जा सचिव विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश...	05
आदिवासी अंचलों में विद्युत विकास योजनाओं का असर	06
कोरबा में बिजलीघरों व जिले में विकास कार्यों की समीक्षा	08
उच्चदाब ट्रांसमिशन टॉवर की डिजाइनों का आदान-प्रदान	09
आंधी आये या तूफान... हम खड़े हैं सीना तान...	10
आपदा में बिजली आपूर्ति, कैसी-कैसी दिक्कतें ...	12
योग दिवस पर पॉवर कंपनी मुख्यालय में सामूहिक योग	14
जिला परिक्रमा : कांकेर	15
मेरा संस्थान-मेरी शान : 6 कोरबा पश्चिम औषधालय	16
टिफिन लाने से राहत, कार्य स्थल पर पांच रुपए में भोजन	17
132 केवी उपकेन्द्र मल्हार ऊर्जित	19
अनवरत विद्युत विकास	20
बिजली की कहानी - 5	26

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में
डबल सब्सिडी की सौगात
छत्तीसगढ़ शासन ने भी दी सहायता
बढ़ेंगे हाफ बिजली बिल से
शून्य बिजली बिल की ओर



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 18 जून 2025 को आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह अति महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि हितग्राहियों को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाए। राज्य सरकार की वित्तीय सहायता केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होगी।

राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त वित्तीय सहायता के पश्चात 1 किलोवॉट, 2 किलोवॉट तथा 3 किलोवॉट और उससे अधिक क्षमता के सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने पर मिलने वाली कुल सहायता की राशि क्रमशः 45,000 रू., 90,000 रु. तथा 1,08,000 रु. हो जाएगी।

इस तरह 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट के लिए केंद्र सरकार की सब्सिडी 30,000 रु. तथा राज्य सरकार की सब्सिडी 15,000 रु. होगी। यदि बैंक द्वारा 6.5 प्रतिशत की दर से आसान किश्तों में 10 वर्षों के लिए ऋण लिया जाए तो इस श्रेणी के उपभोक्ता को मासिक ईएमआई मात्र 170 रु. ही देनी होगी। 2 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट के लिए केंद्र सरकार की सब्सिडी 60,000 रु. तथा राज्य सरकार की सब्सिडी 30,000 रु. होगी। यदि बैंक द्वारा 6.5 प्रतिशत की दर से आसान किश्तों में 10 वर्षों के लिए ऋण लिया जाए तो इस श्रेणी के उपभोक्ता को मासिक ईएमआई मात्र 341 रु. ही देनी होगी। इस तरह 3 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट के लिए केंद्र सरकार की सब्सिडी 78,000 रु. तथा राज्य सरकार की सब्सिडी 30,000 रु. होगी। यदि बैंक द्वारा 6.5 प्रतिशत की दर से आसान किश्तों में 10 वर्षों के लिए ऋण लिया जाए तो इस श्रेणी के उपभोक्ता को मासिक ईएमआई मात्र 818 रु. ही देनी होगी। उल्लेखनीय है कि इस योजना के प्रावधान के तहत 3 किलोवॉट तक का सोलर पॉवर प्लांट लगाने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी।

मंत्रिमण्डल के फैसले के अनुसार हाउसिंग सोसाइटी/रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के लिए भी इसी तरह की सहायता प्रस्तावित की गई है। यह अनुदान राशि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को अग्रिम रूप से मिलेगी और वही इसे लाभार्थियों को देगी। वर्ष 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इससे वित्तीय वर्ष 2025-26 में 180 करोड़ एवं 2026-27 में 210 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी होगी और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार इसे लागू करेगी। कंपनी इस योजना के संचालन के लिए एक अलग बैंक खाता खोलेगी, जिसमें सब्सिडी की राशि रखी जाएगी और उसका हिसाब-किताब किया जाएगा। राज्य वित्तीय सहायता उन घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता से दी जाएगी जिनके सोलर प्लांट का ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद हुआ है।

इस योजना में उपभोक्ता के घर की छत पर लगा सोलर पॉवर प्लांट ग्रिड से जुड़ा होगा जिसके कारण अपने घर की छत पर उत्पादित बिजली का उपयोग अगर उपभोक्ता स्वयं नहीं कर पाएगा

सोलर प्लांट क्षमता	केंद्र सरकार की सब्सिडी	राज्य सरकार की सब्सिडी	कुल सहायता राशि	आसान मासिक EMI
1 KW	रु. 30,000	रु. 15,000	रु. 45,000	रु. 170
2 KW	रु. 60,000	रु. 30,000	रु. 90,000	रु. 341
3 KW	रु. 78,000	रु. 30,000	रु. 1,08,000	रु. 818

- 6.5% ब्याज दर पर आसान बैंक ऋण
- मासिक बिल से भी कम EMI में लगेगा रूफटॉफ सोलर प्लांट
- 10 वर्षों में बैंक ऋण मुक्ति लेकिन प्लांट चलेगा आजीवन



तो उसका समायोजन छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में होगा अतः उपभोक्ता इस अतिरिक्त उत्पादित बिजली को बेचकर अतिरिक्त कमाई कर सकेगा और बिजली उपभोक्ता से प्रदेश और देश के लिए ऊर्जा दाता बन सकेगा।

रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट लगाने में होने वाले खर्च की वसूली 10 वर्षों के अंदर हो जाएगी लेकिन उपभोक्ता को आजीवन लाभ मिलता रहेगा। आवेदन प्रक्रिया की अधिक जानकारी के लिए क्यूआर कोड तथा लिंक की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके लिए लिंक है-https://pmsuryaghar.gov.in

भारत के एक करोड़ घरों का लक्ष्य

''प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना'' जिसकी शुरूआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 को बहु-आयामी लक्ष्यों के साथ की थी। प्रत्यक्ष रूप से दिखने में पीएम सूर्यघर योजना वर्ष 2026-27 तक भारत के एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पॉवर प्लांट स्थापित करने को लेकर है।

ऑनलाइन आवेदन

पहला सवाल तो यही है कि क्या इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे? तो इसका जवाब है, कदापि नहीं। आवेदन के लिए सबसे पहले आपको पीएम सूर्यघर के पोर्टल पर जाकर पंजीयन कराना पड़ेगा। इस तरह पंजीयन कराते ही आपके रास्ते खुल जायेंगे। पोर्टल में पहले राज्य का चुनाव करें, फिर अपनी बिजली वितरण कंपनी को चुनें। फिर अपना उपभोक्ता नंबर डाले और अपना मोबाइल नंबर डालकर मेल भेज दीजिये। इस तरह आपके कन्ज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर से लॉग इन करने के साथ ही रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट के आवेदन का मार्गप्रशस्त हो जायेगा। उसी पोर्टल में आपको अनुमोदन प्राप्त होगा और विद्युत वितरण कंपनी में पंजीकृत वेंडरों के नाम भी आ जायेंगे। अब वेंडर और राज्य विद्युत वितरण कंपनी का अमला सक्रिय हो जायेगा और आपका काम आसान हो जायेगा। आपका इंस्टालेशन पूरा होने के बाद उसी पोर्टल में आपको अपने पीएम सूर्यघर का विवरण भेज कर नेट मीटर के लिए आवेदन करना है। आगे का काम फिर विद्युत वितरण कंपनी का है। इस तरह आपको सब्सिडी भी मिल जायेगी और आपकी छत पर लगे बिजलीघर का काम चलने लगेगा।

यह आकलन है कि तीन किलोवॉट के सोलर पॉवर प्लांट में औसतन हर माह 300 यूनिट बिजली का उत्पादन होता है। यह बिजली आपको निःशुल्क मिलती है। और यदि किसी कारण से यह बिजली आपके घर में उपयोग न हो पाये तो राज्य वितरण कंपनी में इसके समायोजन की व्यवस्था भी है। ताकि उत्पादित बिजली का लाभ आपको हर हालत में मिले। भारत सरकार ने इस योजना के लिए बैंकों से 6.5 से लेकर 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की है।

यह योजना आपको सीधे लाभ दिलाने के साथ ही देश और दुनिया के सरोकारों से भी जोड़ती है। इस संदर्भ में यूनाईटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाईमेट चेंज, से लेकर 26वें यूनाईटेड नेशंस क्लाईमेट चेंज कांफ्रेस (सीओपी 26 ग्लासगो) तक पर गौर करे तो दुनिया की सबसे बड़ी चिंता कॉर्बन उत्सर्जन को लेकर ही सामने आती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कॉर्बन उत्सर्जन (नेट जीरो कॉर्बन एमीशन) की घोषणा जितनी महत्वपूर्ण है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए भारत सरकार के संकल्प और प्रयास। फॉसिल फ्यूएल (जीवाश्म ईंधन) पर निर्भरता समाप्त करने की दिशा में वर्ष 2020 तक 50 प्रतिशत गैर जीवाश्म ऊर्जा स्त्रोंतों से बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य बेहद महत्वाकांक्षी है। भारत ने अपना लक्ष्य खुद ही 175 से बढ़ाकर 500 गीगावॉट कर लिया है। सौर ऊर्जा के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा के हर उपाय को आजमाया जा रहा है। ग्रे हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन ऊर्जा अभियान का शंखनाद भी कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) से लेकर पवन ऊर्जा तक के लिए उदार नीतियों का बड़ा योगदान दर्ज करने की तैयारी है।





आदिवासी अंचलों और घरों में बिजली पहुंचाने की मुहिम तेज

छत्तीसगढ़ राज्य में नवंबर सन् 2000 की स्थिति में 17108 गांव विद्युतीकृत थे। सन् 2018-19 में 19609 गांवों के विद्युतीकरण के साथ ही शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था। तत्पश्चात प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शत-प्रतिशत घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया। इस कार्य के लिए किए गए सर्वे में यह पाया गया कि छत्तीसगढ़ में जनजाति ग्रामों के 34036 घर तथा गैर जनजाति ग्रामों के 31675 घरों में बिजली नहीं पहुंची है। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में 7 विशेष पिछड़ी जनजातियों के लोग निवास करते हैं। जिसमें बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया, भारिया, बिरहोर और शहरिया जनजाति शामिल हैं। इन जनजातियों के 7077 घर भी बिजली की रोशनी से वंचित थे। इस तरह भारत सरकार ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान तथा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा-अभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत इस सभी घरों में बिजली पहुंचाने की योजना बनाई तथा इसके लिए केंद्र, राज्य तथा पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंशदान का निर्धारण किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अधोसंरचना विकास योजना, मजराटोला विद्युतीकरण योजना के अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित सीआरपीएफ कैम्पों के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित गांवों में 7946 घरों को ग्रिड से विद्युतीकृत करने की योजना बनाकर अमल में लाई जा रही है। इस प्रकार आदिवासी अंचलों में 80801 घरों को ऑन-ग्रिड बिजली से रोशन करने का महा अभियान प्रगति पर है।

▪ प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा-अभियान

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की 07 विशेष पिछड़ी जनजातियों (पी.वी.टी.जी.) यथा बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया, भारिया, बिरहोर एवं शहरिया जनजाति का चयन पीएम-जनमन योजना में उन्हें मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। विद्युत की उपलब्धता उनमें से एक है। छत्तीसगढ़ राज्य के 18 जिलों में इन पी.वी.टी.जी. घरों का सर्वे कर 7077 अविद्युतीकृत घरों को ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा राशि रु 37.6 करोड़ की डीपीआर स्वीकृति प्रदाय की गई। इस योजना की लागत हेतु केन्द्र का 60 प्रतिशत, राज्य का 10 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का 30 प्रतिशत अंशदान है। 16 जून 2025 तक 7144 घरों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

▪ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एवं अतिरिक्त घरों का विद्युतीकरण

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान





बस्तर पहुंचे ऊर्जा सचिव डॉ.रोहित यादव, विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश...

छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा सचिव तथा उत्पादन व वितरण कंपनियों के अध्यक्ष डॉ रोहित यादव ने 24-25 मई को बस्तर स्थित क्षेत्रीय मुख्यालय जगदलपुर का दौरा किया ।उनके साथ पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री भीमसिंह कंवर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी थे। डॉ यादव ने कलेक्टरेट परिसर के सभागार में बैठक ली और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की । उन्होंने मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना तथा मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना से आदिवासी अंचलों को तेजी से लाभान्वित करने के निर्देश दिये। उन्होंने सुकमा जिले के जगरगुंडा तथा बीजापुर जिले के भद्रकाली व गंगालूर उपकेन्द्रों ,132/33 केवी उपकेन्द्र जामगांव का निर्माण शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये । चिंतागुफा में 33/11 केवी उपकेन्द्र के लिये प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये। जगदलपुर में स्टॉफ क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव भेजने व संचालन- संधारण कार्यों में विशेष ध्यान देने को कहा। हर घर में बिजली पंहुचाने वाली केंद्रीय योजनाओं तथा क्षेत्रीय विकास के लिए अन्य योजनाओं के साथ ही नियद नेल्लानार योजना को तेजी से पूरा करने के निर्देश भी डॉ.यादव ने दिये।

का प्रमुख उद्देश्य मुख्य रूप से जनजातीय गांवों में निवासरत जनजातीय परिवारों को आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

इस पहल के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ राज्य (जनजातीय ग्रामों) में अविद्युतीकृत घरों की संख्या 34036 है, जिसमें सरगुजा राजस्व संभाग के 12995 घर एवं बस्तर राजस्व संभाग के 12498 घर शामिल है। इसी प्रकार इसके अलावा गैर-जनजातीय गांवों में यह संख्या 31675 है, जिसमें सरगुजा राजस्व संभाग के 7862 घर एवं बस्तर राजस्व संभाग के 7289 घर शामिल है। इस प्रकार कुल 65711 घरों (जनजातीय ग्रामों के 34036 घर एवं गैर-जनजातीय ग्रामों के 31675 घर) बिना विद्युतीकरण के हैं। इन 65711 घरों के विद्युतीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा 4 अक्टूबर 2024 को रु. 323.63 करोड़ की डीपीआर स्वीकृति प्रदाय की गई है।

इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निधियों की स्वीकृति निम्नानुसार दी गई है। केंद्रांश 60 प्रतिशत, राज्यांश 10 प्रतिशत और सीएसपीडीसीएल द्वारा ऋण 30 प्रतिशत।

कार्य की स्थिति: 16 जून 2025 की स्थिति में 7 पैकेज के अंतर्गत कुल 27745 घरों का कार्यादेश, ठेकेदारों को जारी किया जा चुका है एवं 6 पैकेज के अंतर्गत कुल 37966 घरों का कार्यादेश प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

▪ नियद नेल्लानार योजना

नियद नेल्लानार योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित सीआरपीएफ कैंपों के 5 किमी के दायरे में स्थित गांवों का चयन समग्र विकास हेतु किया गया है। इस योजना का उद्देश्य इन दूरस्थ क्षेत्रों के निवासियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करना है, जिसमें घरों का विद्युतीकरण और अन्य आवश्यक विकास कार्यक्रम शामिल हैं।

प्रारंभ में राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 71 गांवों के कुल 169 बसाहटों एवं 30 सीआरपीएफ कैंपों का चयन किया है, जो बस्तर राजस्व संभाग के बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा जिलों में स्थित हैं। ये गांव पहले ही ऑफ-ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत हो चुके हैं जिन्हें अब ग्रिड से जोड़ा जाना है। 71 गांवों के 7946 घरों और 30 सीआरपीएफ कैंपों को ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा 27 मार्च 2025 को राशि रु. 55.68 करोड़ की डीपीआर स्वीकृति प्रदाय की गई है। इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 60 प्रतिशत, राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत अंशदान किया जाना है। डीपीआर राशि के अलावा अतिरिक्त राशि का योगदान गृहमंत्रालय, भारत सरकार द्वारा

आदिवासी अंचलों में विद्युत विकास योजनाओं का असर

किया जाएगा।

अद्यतन स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 58 गांवों के 6482 घरों के विद्युतीकरण हेतु कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं। शेष 13 गांवों के 1464 घर निविदा प्रक्रिया में हैं। 16 जून 2025 की स्थिति में कुल 1931 घरों का ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

▪ छिंदौला (जिला गरियाबंद)



गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखण्ड का छिंदौला गांव मुख्यतः कमार जनजाति बहुल बस्ती है। ग्राम पंचायत दबनई के आश्रित गांव छिंदौला में आजादी के 75 वर्ष बाद मई 2024 में बिजली पहुंची। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत यहां बिजली पहुंचाने का कार्य किया गया। श्री विष्णुदेव साय के मुख्य मंत्रित्व में गठित सरकार ने आदिवासी अंचलों में विकास को प्राथमिकता देते हुए जब गांव-गांव में शिविर लगाकर समस्याओं की जानकारी ली तब छिंदौला में बिजली की समस्या पर ध्यान गया। यहां कमार जनजाति के लगभग 40 घरों में बिजली पहुंचाने के लिए तैयारी की गई। घने जंगल के बीच बसे होने के कारण इस गांव में बिजली पहुंचाने का काम चुनौतीपूर्ण था। गांव वालों ने बताया कि पारिवारिक, मांगलिक, सामाजिक कार्यों में तो दिक्कत होती ही थी मोबाइल चार्ज करने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था। छिंदौला निवासी श्री कंवल सिंह, श्री जगतराम, श्री सखाराम, श्री फगनुराम, श्रीमती रामबती, श्रीमती बिसाहीन बाई, श्रीमती देवली बाई आदि ने इस सौगात के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद प्रेषित किया।

▪ सुकड़ीगुहान (जिला बालोद)

बालोद जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंघोला के आश्रित पारा सुकड़ीगुहान में कमार जनजाति



के लोग निवास करते हैं। इस बस्ती के 10 घरों में बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण यहां के लोग असुविधाओं में जीवनयापन कर रहे थे। विद्युत वितरण कंपनी के गुरूर उपसंभाग के अधिकारियों ने यहां की खोज-खबर ली जिससे श्री महादेव नेताम, श्रीमती शांति बाई, श्री अंकालु, श्री अजय कुमार, श्री सगन, श्री धीरजुराम, श्री देसीराम, श्री बुधारू, श्री धीरज और श्री सोमनारू राम के घर में अगस्त 2024 में बिजली कनेक्शन दिया गया। ये परिवार सूपा, चरिहा, टोकरी आदि बनाकर जीवनयापन करते हैं। बिजली की सुविधा मिल जाने से अब ये लोग रात में भी कार्य कर सकेंगे और बच्चों का भविष्य भी संवार सकेंगे। बताया गया कि पहले तो ये बिजली से डर रहे थे लेकिन अधिकारियों द्वारा समझाइश देने पर इन्होंने बिजली का स्विच ऑन-ऑफ करना सीखा।

▪ महुआपनी (जिला जशपुर)



जशपुर जिला मुख्यालय से 85 किलोमीटर दूर स्थित सुलेसा ग्राम पंचायत के आश्रित गांव महुआपनी में विशेष पिछड़ी कोरवा जनजाति के 100 से अधिक परिवार निवास करते हैं। यह पहाड़ी क्षेत्र जंगलों से घिरा है। ग्रामीणों ने बिजली लगाने के लिए मुख्यमंत्री के बगिया स्थित कैंप कार्यालय में आवेदन दिया था जिसके कारण पीएम जनमन योजना के माध्यम से यहां बिजली पहुंचाई गई। यहां के निवासी श्री आलुराम, श्री भदई राम, श्री खुलु पैंकरा, श्री रामबिशाल यादव ने उनके घरों में बिजली पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार प्रकट किया है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली न होने से वे कितना पीछे रह गए अब उन्हें यह समझ आ रहा है। बिजली आना उनके लिए एक उत्सव की तरह है। अब उनकी जिंदगी में तरक्की की असली रोशनी आएगी।

▪ भीरालाट, लूठामारा (जिला गरियाबंद)





गरियाबंद जिले के मैनपुर मार्ग के किनारे ग्राम पंचायत जोवा के आश्रित ग्राम भीरालाट में 18 कमार जनजाति परिवार निवास करते हैं। चारों तरफ जंगलों से घिरे इस गांव में वन्यप्राणियों का खतरा तो होता ही है, अंधेरे की वजह से अनेक तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस गांव में बिजली पहुंचाने के लिए भी पीएम जनमन योजना वरदान साबित हुई। इस अंचल में लूठामारा गांव में अप्रैल में बिजली आ गई थी जिसके कारण यहां के लोगों ने बिजली की सुविधा की मांग की थी और जुलाई माह में भीरालाट के घर भी बिजली से रोशन हो गए।

▪ तिमेनार (जिला बीजापुर)

बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकासखंड के ग्राम बेचापार के आश्रित गांव तिमेनार में बिजली नहीं पहुंची थी। मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतीकरण योजना के तहत अप्रेल 2025 में इस गांव का



विद्युतीकरण कराया गया और 53 घरों में बिजली पहुंचाई गई। यह बसाहट माओवादी आंतक से काफी समय से प्रभावित रहा हैं जिसके कारण बुनियादी सुविधाओं से अछूता रह गया था। गांव के निवासी श्री मशराम पंडरू कुंजाम मंगली प्रमिला बेको आदि ने बताया कि बिजली आने से उनके गांव का माहौल बदल गया है और उन्हें यह उम्मीद जगी है कि उन्हें सरकार की प्रत्येक जनहितकारी योजना का लाभ मिलेगा। जहां कहीं आंतक एवं अंधकार का बोलबाला था वहां अब तेजी से विकास होगा।

पुसकोंटा (जिला बीजापुर)



बीजापुर जिले के सुदूर अंचल में स्थित ग्राम पंचायत हीरापुर के आश्रित गांव पुसकोंटा में नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत बिजली पहुंचाई गई है। यहां के ग्रामीणों श्री देवा कुंजाम, श्री भीमा मण्डावी, श्री नागू कोटटाम, श्रीमती जमुना मिच्चा ने बताया कि बिजली की रोशनी होने से रात को जंगली जानवरों का डर समाप्त हो गया है। बिजली आने से घरों में नल से पानी आने लगा है। गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिलने लगा है। गांव में पहली बार बिजली आने से हौसला बहुत बढ़ गया है।

▪ टेकलगुड़यम (जिला सुकमा)



सुकमा जिले के कोटा विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत पेंटाचिमली के अंतर्गत ग्राम टेकलगुड़यम को नियद नेल्लानार योजना से बिजली की रौशनी मिल गई है। इस गांव के 75 घरों में बिजली कनेक्शन लगने से बच्चों से लेकर बुजुर्गो तक में नई आशा और उत्साह का संचार हुआ है। इस गांव के युवा शिक्षा, स्वास्थ और रोजगार के अवसरों के साथ ही डिजिटल सेवाओं से अपना भविष्य संवारने के प्रति भी आश्वस्त हुए है।

▪ पालनार (जिला बीजापुर)



बीजापुर जिले के ग्राम पंचायत पालनार को माओवादी के गढ़ के रूप में माना जाता रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की नियद नेल्लानार योजना के तहत इस गांव में विद्युतीकरण और मोबाइल टॉवर लगाने का कार्य किया गया है। इस क्षेत्र में बसाहट दूर-दूर होने के बावजूद 300 घरों में बिजली पहुंचाने का कठिन कार्य किया गया है। इससे बहुत सारी नागरिक सुविधाएं यहां पहुंची है। सरपंच शिल्पी मालती तांती तथा श्री भदरू तांती, श्री बुधराम पुनेम आदि ने बताया कि नियद नेल्लानार योजना से बिजली के अलावा भी बहुत से कार्य चल रहे है जिससे उन्हें पहली बार लगा है कि अब उनका जीवन तथा बच्चों का भविष्य सुरक्षित है।

▪ पेद्दागेल्लूर (जिला बीजापुर)



बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के अंतर्गत चिन्नागेल्लूर ग्राम पंचायत के सुदूर गांव पेद्दागेल्लूर को नियद नेल्लानार योजना से बिजली का वरदान मिला है। यहां के निवासी श्री सिंह सोढ़ी रामा ने बताया कि बिजली के अभाव में गांव पूरी तरह से विकास से दूर रहा। गांव वालों को न तो सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पाता था और न ही उन्हें अपने परिवार और बच्चों की तरक्की का रास्ता। बिजली आने से गांव का माहौल एकदम बदल गया है। कक्षा तीसरी की छात्रा सुशीला ओयाम बताती है कि अब रात को पढ़ने की कोशिश में आंखें नहीं दुखती बल्कि बिजली की रोशनी के कारण वह अच्छे से पढ़ाई कर पा रही है और बड़ी होकर शिक्षिका बनेगी ताकि गांव के लोगों की जिंदगी में शिक्षा का उजाला भर सके। इस गांव में अब 192 घरों में बिजली का कनेक्शन जुड़ गया है।

▪ मुदवेंडी (जिला बीजापुर)



बीजापुर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित मुदवेंडी गांव के 145 परिवार आतंक के साय में जी रहे थे। श्री हीरा कुंजाम ने बताया कि नियद नेल्लानार योजना से उनके गांव में बिजली आ गई है, साथ ही 145 घरों में भी बिजली का प्रकाश होने लगा है। गांव में बरसों से बंद पड़ी स्कूल का संचालन भी शुरू हो गया है। गांव के युवा श्री लखमा कुंजाम का कहना है कि पहली बार उन्हें लगा है कि उनका भविष्य सुरक्षित हुआ है। वे बेहतर रोजगार करके अपना और परिवारजनों का जीवन संवार पाएंगे।

▪ तर्रा-बसेर-मेंद्रा (जिला कोरिया)



कोरिया जिले के ग्राम तर्रा, बसेर और मेंद्रा में बिजली आने की कहानी कुछ अलग ही है। ग्राम पंचायत बसेर के सरपंच श्री नाहर सिंह ने बताया कि सन् 1997-98 में कुछ स्थानों पर बिजली के खंभे लगाए गए थे तो उम्मीद जागी थी कि बिजली आ जाएगी लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि खंभे बिजली लाइनों के लिए तरसते रह गए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार ने मजराटोला विद्युतीकरण योजना के तहत इन गांवों में लाइनें और ट्रांसफॉर्मर लगवाए। ग्राम तर्रा में 55 लाख रू. की लागत से 12 किमी 11 केवी और 9 किमी एलटी लाइन बिछाई गई। 3 ट्रांसफॉर्मर लगाए गए और 88 घरों को बिजली कनेक्शन मिला। ग्राम बसेर में 1.08 करोड़ रू. की लागत से 8 किमी 11 केवी और 6 किमी एलटी लाइन का विस्तार हुआ। 7 ट्रांसफॉर्मर लगाए गए और 230 घरों में बिजली पहुंची। ग्राम मेंद्रा में 54 लाख रू. की लागत से 9 किमी 11 केवी और 6 किमी एलटी लाइन बिछाई गई। 2 ट्रांसफॉर्मर लगाए गए और 64 घरों में बिजली की सप्लाई शुरू हुई। आजादी के 77 साल बाद अंधेरे से आजादी पाने का सुख अब इन गांव वालों को मिल रहा है।





अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव के साथ प्रबंध निदेशक श्री कटियार एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी

कोरबा में बिजलीघरों व जिले में विकास कार्यों की समीक्षा





छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा सचिव तथा उत्पादन एवं वितरण कंपनियों के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव ने 10 से 12 अप्रैल तक कोरबा जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिले में सामान्य विकास कार्यों, केंद्र व राज्य सरकार की फ्लैगशिप विद्युत विकास योजनाओं की समीक्षा की तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए।

डॉ. यादव ने इस दौरान कोरबा जिले के कुछ ग्रामों का दौरा किया तथा योजनाओं के क्रियान्वयन का अवलोकन किया। उन्होंने कलेक्टरेट परिसर में जिला अधिकारियों की बैठक ली। डॉ. यादव ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, हसदेव ताप विद्युत गृह की सभी इकाईयों के साथ ही हसदेव बांगों जल विद्युत गृह, कोरबा पूर्व तथा कोरबा पश्चिम के विभागीय अस्पतालों का अवलोकन भी किया। उन्होंने 2 660 मेगावॉट क्षमता की नई सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट स्थल का अवलोकन किया। उन्होंने विद्युत गृह परिसर में पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विद्युत संयंत्रों की कार्यप्रणाली और उपलब्धियों का अवलोकन किया। डॉ. यादव ने विद्युत गृहों के बेहतर संचालन हेतु यथोचित मार्गदर्शन भी प्रदान किया।





उच्चदाब ट्रांसमिशन टॉवर की डिजाइनों का आदान-प्रदान करेंगे म.प्र. व छत्तीसगढ़



छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के अध्यक्ष श्री सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि प्रौद्योगिकियों के परस्पर विनिमय से सभी पक्षों की दक्षता बढ़ती है। इसका लाभ दोनों राज्यों को मिलना सुखद है। प्रौद्योगिकीय उन्नयन से ही भावी चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा।



छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री राजेश कुमार शुक्ला ने कहा कि दोनों कंपनी के आपसी सहयोग व तकनीक साझेदारी का लाभ दोनों राज्यों को मिलेगा। इससे अत्याधुनिक पारेषण प्रणाली, तकनीक और प्रशिक्षण का आदान-प्रदान हो सकेगा।



छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी का तकनीकी ज्ञान अब मध्यप्रदेश के विद्युत विस्तार में योगदान देगा। छत्तीसगढ़ 400 केवी के टॉवर की डिजाइन मध्यप्रदेश को देगा और मध्यप्रदेश के 220 केवी और 132 केवी के टॉवर की डिजाइन लेगा। इस तकनीक व कौशल के आदान-प्रदान से दोनों प्रदेश की पॉवर कंपनियों को लाभ होगा। इस नई व्यवस्था से ट्रांसमिशन कंपनी के विशाल टॉवरों की स्थापना में कम भूमि की जरूरत पड़ेगी।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी और मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के बीच जबलपुर के शक्ति भवन में अनुबंध हुआ। इसमें छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के कार्यपालक निदेशक (योजना, वाणिज्यिक एवं विनियामक मामले) श्री के. एस. मनोठिया और मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के कार्यपालक निदेशक श्री समीर नगोटिया (वाणिज्यिक एवं विनियामक मामले) ने हस्ताक्षर किये। इस अवसर पर एमपीपीटीसीएल के प्रबंध निदेशक श्री सुनील तिवारी विशेष रूप से उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी को 400 केवी अति उच्च दाब टॉवर स्थापित करने में विशेष दक्षता हासिल है। इसकी डिजाइन को छत्तीसगढ़ ने केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) बैंगलोर को भेजा था, जहां वेटिंग, चेकिंग और स्क्रूटनी के पश्चात् टॉवर स्ट्रक्चर की डिजाइन को बेहतर माना गया।

वहीं मध्यप्रदेश में 220 केवी और 132 केवी के अतिउच्च दाब टॉवर की नेरो बेस डिजाइन बेहतर मानी जाती है, जिसमें कम जमीन का उपयोग करते हुए सकरे फाउंडेशन में विशाल टॉवर खड़े किये जाते हैं। खासकर शहर में जमीन की उपलब्धता कम होने पर इस डिजाइन की अधिक आवश्यकता थी। इस डिजाइन में जहां सामान्य टॉवर के लिए जो जगह फाउंडेशन में लगती थी उससे अब लगभग आधी जगह लगेगी। इससे टॉवर स्थापित करने में लगने वाली किसानों की कम जमीन प्रभावित होगी। मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने इन दोनों टॉवर की डिजाइन देने के एवज में 2.89 करोड़ रुपए का शुल्क मांगा गया था। अब छत्तीसगढ़ के 400 केवी टॉवर की डिजाइन के बदले मध्यप्रदेश 220 केवी और 132 केवी नैरो बेस डिजाइन साझा कर रहा है, इससे छत्तीसगढ़ को 2.89 करोड़ रुपए की सीधी बचत हो रही है।

छत्तीसगढ़ ट्रांसको के प्रबंध निदेशक श्री राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि यह साझेदारी दोनों राज्यों की ऊर्जा अवसंरचना को और अधिक सक्षम बनाएगी तथा टेक्नो कमर्शियल क्षेत्र मे बड़ा नवाचार होगा। यह एक 'मील का पत्थर' साबित होगा, जो भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। यह समझौता न केवल दोनों राज्यों के तकनीकी विकास को गति देगा, बल्कि क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को भी नई दिशा प्रदान करेगा। इस अवसर पर मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य अभियंता श्री देवाशीष चक्रवर्ती, अधीक्षण अभियंता श्री सुधीर नेमा तथा छत्तीसगढ़ ट्रांस्को से कार्यपालन अभियंता श्री टी. के. कुंभज उपस्थित थे। इस सहयोग का प्रमुख उद्देश्य विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता को बढ़ाना, तकनीकी दक्षता में सुधार लाना तथा संचालन और रखरखाव की लागत को न्यूनतम करना है।

आंधी आये या तूफान...







दिन-रात एक करके बिजली कर्मियों ने लौटाई रोशनी

हर साल गर्मियों में मौसम बदलने और मानसून के पहले आंधी-तूफान का एक विध्वंसक दौर आता है, जिसमें आम जनजीवन बहुत ही बुरी तरह प्रभावित होता है। इससे कच्चे घरों की छत-छानी उड़ जाती है। खपरैल उड़ जाते हैं। निजी व सार्वजनिक सुविधाओं के लिये बनी कई प्रकार की अधोसंरचना ढह जाती है। इस वर्ष तो टोल नाके पर बना लोहे और सीमेंट कांक्रीट का बना स्ट्रक्चर ही ढह गया। बड़े पैमाने पर वृक्ष गिरने, टहनियां टूटने और बड़ी तेजी से उड़ने के कारण जान-माल की क्षति होती है। मवेशियों की मौत होती है। बिजली गिरने से भी जान-माल की क्षति होती है। ऐसे वातावरण में बिजली की अधोसंरचना भी बड़े पैमाने पर प्रभावित होती है। जगह-जगह पारेषण और वितरण तंत्र को नुकसान पहुंचता है। बिजली के खंभों, लाइनों सहित अन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचने के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित होने से लोगों का पूरा ध्यान बिजली बंद होने पर आकर टिक जाता है। पॉवर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मैदानी अमले के लिये यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। आंधी-तूफान-बारिश के बीच फाल्ट खोजने का काम काफी जोखिमपूर्ण भी होता है। बिजली की लाइनें खेत-खलिहान-नदी-घाटी-जंगल-दुर्गम

हम खड़े हैं सीना तान...



और निर्जन स्थानों से भी गुजरती हैं और बड़े शहरों-गांवों-कस्बों-बसाहटों से भी। शहरों में भी कई इलाके कठिन होते हैं। बिजली कर्मी ऐसी परिस्थितियों में पूर्व निर्धारित प्राथमिकता क्रम में कार्य करते हैं ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके। रेस्टोरेशन के काम इस बात पर निर्भर करते हैं कि अनायास आई आपदा से किस तरह की क्षति हुई है। इसलिये इस विषय पर यह तुलना उचित नहीं होती कि पिछली बार तो इतने मिनट में बिजली आ गई थी। अनायास प्रशिक्षित बिजली कर्मियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ाना भी संभव नहीं होता लेकिन फिर भी मैदानी अधिकारीगण हर संभव व्यवस्था करते हैं कि आसपास उपलब्ध प्रशिक्षित अमले का जुगाड़ हो जाये और संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल हो। दिन-रात एक करके मैदानी अमला रेस्टोरेशन की चुनौती से जूझता है। इस दौरान अनेक स्थानों पर उन्हें जन आक्रोश का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि प्रभावित उपभोक्ताओं को बिजली कर्मियों की परेशानियों का ज्ञान नहीं होता। उन्हें बस यही लगता है कि फलां जगह की बिजली पहले आ गई तो हमारे यहां की क्यों नहीं आई। बिजली कर्मी इस दौरान जोखिमों और चुनौतियों का सामना करते हुये इतने थके होते हैं कि वे भीड़ को समझाने की स्थिति में नहीं होते।



बिजली कर्मियों के सामने तो एक ही लक्ष्य होता है कि किस तरह जल्दी से जल्दी बाकी जगहों पर बिजली आपूर्ति को सामान्य बनायें।

1 मई 2025 को और उसके आसपास जो आंधी-तूफान का सिलसिला शुरू हुआ था उसमें 1300 से अधिक बिजली के खंभे, 1500 के करीब लाइनें क्षतिग्रस्त हुई थी। विभिन्न स्थानों पर सैकड़ों फीडर बंद हो गए थे। शाम को आए आंधी-तूफान के बाद जल्दी ही अंधेरा घिरने लगा था और बिजली कर्मियों की चुनौतियां भी गहराने लगी थी। ऐसे में रेस्टोरेशन कार्य पर नजर रखने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वयं मुख्यमंत्री सचिवालय में व्यवस्था की और लगातार सुधार कार्यों की जानकारी लेते रहे। तत्कालीन प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री सुबोध सिंह, प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी श्री भीमसिंह कंवर ने क्षेत्रीय मुख्यालयों में पदस्थ कार्यपालक निदेशकों तथा मुख्य अभियंताओं से लगातार संपर्क बनाए रखा तथा आवश्यक निर्देश प्रदान करते रहे। मैदानी स्तर पर संचारण-संधारण निकाय के अतिरिक्त लाइनों के संधारण एवं मॉनीटरिंग कार्य हेतु सतर्कता विभाग, एसटीएम विभाग, परियोजना संकाय के अधिकारियों-कर्मचारियों एवं बाह्य स्त्रोतों से प्राप्त



मानव संसाधनों की टीम गठित कर त्वरित गति से सुधार कार्य किया गया। जिसके कारण शहरी अंचलों में तो एक घंटे से लेकर चार घंटे तक अर्थात् मध्य रात्रि तक विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बस्तियों में पेयजल आपूर्ति की प्राथमिकता को देखते हुए सुधार कार्य किए गए। कृषि कनेक्शनों तथा वन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बहाल करने का काम दूसरे दिन हो पाया। 1 मई के पश्चात भी रायपुर क्षेत्र, रायपुर ग्रामीण क्षेत्र, राजनांदगांव क्षेत्र, दुर्ग क्षेत्र, बिलासपुर क्षेत्र, सरगुजा क्षेत्र, रायगढ़ क्षेत्र तथा जगदलपुर क्षेत्र में बार-बार आंधी-तूफान की घटनाएं होती रही। स्थानीय अमलें के साहसिक तथा उत्साहपूर्ण योगदान से सभी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रारंभ की गई।

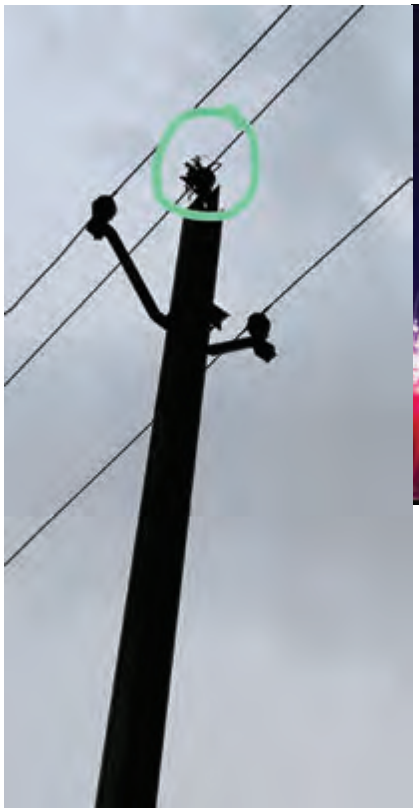



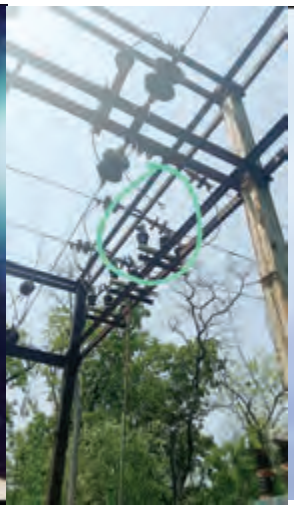



आपदा में बिजली आपूर्ति, कैसी-कैसी दिक्कतें ...

प्राकृतिक आपदा यानी आंधी-तूफान, बाढ़, अग्निकांड व ऐसी ही अन्य दुर्घटनाओं के समय बिजली आपूर्ति बंद होने के अनेक कारण होते हैं। आपदा से विद्युत प्रणाली को बचाने के लिए कुछ ऐसे इंतजाम किए जाते हैं जो एक झटके में सारी प्रणाली को ध्वस्त होने से बचा लेते हैं। जैसे बिजली चमकने और गिरने से विद्युत प्रणाली को बचाने के लिए लाइटेनिंग अरेस्टर लगाए जाते हैं जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर (वीसीबी) को ट्रिप कर देते हैं। जो काम घरों में आंतरिक वायरिंग को खतरे या नुकसान से बचाने के लिए एमसीबी करते हैं। एमसीबी के ट्रिप होने के कारण (आंतरिक लाइन) घरेलू उपकरण जैसे टीवी, फ्रीज, एसी, कूलर, माइक्रोवेव आदि जलने से बच जाते हैं। वैसा ही काम फीडरों में पीसीवी करते हैं। बिजली और आंधी की स्थिति सामान्य होने पर फीडरों के प्रत्येक वीसीबी को वापस चालू किया जाता है जिससे कुछ मिनटों बाद ही विद्युत आपूर्ति चालू हो जाती हैं बशर्ते लाइन पर कोई और नुकसान न हुआ हो। शहरों की तुलना में गांवों में बिजली गिरने या हवा की गति तेज होने से दुर्घटना अधिक होती है। बिजली की लाइनों अर्थात् कंडक्टर या तारों पर जब कोई नुकसान होता है तो सबसे पहला काम उस जगह पर फॉल्ट को खोजना होता है। और फिर फॉल्ट को सुधारने का काम किया जाता है। फॉल्ट आने के अनेक कारण होते हैं। आंधी, बिजली तो प्रमुख कारण होता ही है लेकिन वास्तविक तकनीकी समस्या तब आती है जब कंडक्टर पर पेड़, पेड़ की डाली, कपड़ा, रस्सी, प्लास्टिक की शीट, लोहे-लकड़ी-फाइबर आदि के स्ट्रक्चर उड़कर फंस जाते हैं। बिजली टॉवर की संरचना को देखें तो वी-क्रॉस आर्म, पिन इंसुलेटर, टॉप क्लैम्प इंसुलेटर के ऊपर कोई चीज गिरकर फंस जाती है तो लाइन शॉर्ट हो जाती है। डिस्क इंसुलेटर, ट्रांसफॉर्मर डीपी आदि पर भी इस तरह की वस्तुओं का दुष्प्रभाव होता है। पेड़ या पेड़ की डाली जब लाइन पर गिरती है या कोई खंभा जमीन से उखड़ जाता है या झुक जाता है तो यह एक बड़े क्षेत्र की लाइन को नुकसान पहुंचाता है। यह तो फॉल्ट खोजने वालों को आसानी से दिख जाता है लेकिन पिन इंसुलेटर, खंभे के सबसे ऊपरी हिस्से पर चीनी मिट्टी के बने कपनुमा उपकरण के ऊपर निकली पिन, वी-क्रॉस आर्म, डिस्क इंसुलेटर आदि पर कोई छोटा सा कपड़ा या तिनका जैसा बाहरी टुकड़ा फंस जाता है तो वह बहुत आसानी से दिखाई नहीं पड़ता। कई बार उखड़े हुए खंभे को लगाने और उससे जुड़े हुए सारे कनेक्शन ठीक करने में जितना समय लगता है उतना समय फॉल्ट खोजने में भी लग जाता है। विशेषकर वन क्षेत्रों में, नदी-नाले से भरपूर दुर्गम क्षेत्रों में ऐसी स्थिति बनती है। फॉल्ट खोजे बिना अगर लाइन चालू कर दी जाए तो फिर से लाइन शॉर्ट से और भी बड़े नुकसान का खतरा बना रहता है। आसपास के पेड़ की टहनियां तो नियमित













न ही सम्भव। अब सवाल उठता है कि क्या उड़कर आने वाली ऐसी चीजों को रोका जा सकता है जो लाइनों-तारों में उलझकर शॉर्ट सर्किट कर देती हैं ये शॉर्ट सर्किट अन्य परिस्थितियों के कारण छोटी से लेकर बड़ी-बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं तो इसका जवाब है कि नागरिक सतर्कता से तथा स्थानीय निकायों द्वारा नियमों का कड़ाई से पालन किया जाये तो कम से कम आंधी के दौरान बिजली लाइन पर बैनर, होर्डिंग्स, कपड़े-फ्लेक्स शीट को गिरने से रोका जा सकता है। 1-2 मई 2025 की आंधी और मानसून सक्रिय होते तक बहुत बड़े पैमाने में लाइनों के ऊपर उड़कर आई चीजों का व्यवधान देखा गया है जो चिंताजनक है। विद्युत वितरण प्रणाली में ऐसे व्यवधान से जब विद्युत प्रदाय प्रभावित होता है तब उसकी जन प्रतिक्रिया के तेज स्वर सुनाई पड़ते हैं लेकिन आसमान तले कार्य करने वाली विद्युत पारेषण और वितरण प्रणाली के प्रति जनजागरूकता की बेहद कमी है, इस संबंध में आम जनता को विचार और सहयोग करना चाहिए।

रूप से काटकर विद्युत लाइनों से दूर रखी जा सकती हैं। समय-समय पर विद्युत वितरण कंपनी द्वारा यह कार्य कराया जाता है लेकिन बहुत से क्षेत्र ऐसे होते है जहां निजी स्वामित्व या सोसायटी आदि होने के कारण वहां वितरण कंपनी की पहुंच नहीं होती। कई बार सीमित संसाधनों या समुचित सूचना के अभाव में भी बिजली लाइनों के पेड़ों के निकट होने की स्थिति बनती है। यदि आम नागरिक-स्थानीय संस्थाएं भी इसका ध्यान रखें और सहयोग करें तो लाइनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। आजकल होर्डिंग-फ्लेक्स आदि चीजों का उपयोग बढ़ गया है जो तेज हवा के कारण उड़कर बिजली लाइनों के ऊपर गिर जाती हैं और इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। वैसे तो बिजली का पूरा पारेषण-वितरण नेटवर्क ही खुले आसमान के नीचे होता है। इसे शत-प्रतिशत अंडर ग्राउंड कर पाना न तो व्यावहारिक है और





अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर पॉवर कंपनी मुख्यालय में सामूहिक योग

'नियमित योग से बढ़ती है शारीरिक व मानसिक कार्यक्षमता- शुक्ला'

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून 2025 को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़ मुख्यालय डंगनिया रायपुर में योग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह सैकड़ों अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने सामूहिक योग अभ्यास किया। पूरे कार्यक्रम की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की गई, जिसका फायदा फील्ड में पदस्थ पॉवर कंपनी के कर्मचारियों, अधिकारियों, पेंशनरों के अलावा आम जनता ने भी उठाया। अब सभी के लिए पूरे वर्ष निशुल्क ऑनलाइन योग की व्यवस्था भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से की जा रही है।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री राजेश कुमार शुक्ला ने कहा कि योग भारत



की प्राचीन परंपरा है, आज पूरे विश्व में योग को अपनाया जा रहा है। योग अभ्यास से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। स्वस्थ जीवनशैली के लिये योग को दिनचर्या में शामिल करना चाहिये, इससे मन प्रसन्न रहता है और कार्यक्षमता भी बढ़ती है।

पॉवर कंपनी के भार प्रेषण केंद्र परिसर में योग अभ्यास तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। योग विशेषज्ञ डॉ. आनंद भारतीय ने योग प्रशिक्षण एवं अभ्यास कराया। उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों में तनावमुक्त रहने एवं बीमारियों से निदान के लिए भी योग अभ्यास कराये। उनके साथ योग प्रशिक्षक पलाश चंद्राकर एवं प्रदीप सिन्हा सहायक के रूप में उपस्थित थे। अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) श्री विनोद अग्रवाल ने कहा कि भारत में पांच हजार साल पहले से योग की शुरूआत हुई। महर्षि पंतजलि ने योग दर्शन के जरिये इसे सूत्रित किया। आज पूरी दुनिया में योग भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ा रही है। इस अवसर पर ईडी श्री संजय पटेल ने शीर्षासन की प्रस्तुति दी।

योग प्रशिक्षण में पॉवर कंपनी के कार्यपालक निदेशक सर्वश्री संजय पटेल, एमएस चौहान, केएस मनोठिया, सीएमओ डॉ. एचएल पंचारी सहित सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता पीएन सिंह, अविनाश सोनेकर, पीके जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक (जनसंपर्क) गोविन्द पटेल ने किया।



कांकेर

वर्ष 1998 में बस्तर जिला से पृथक होकर कांकेर जिला अस्तित्व में आया। कांकेर जिला में कुल आबाद ग्रामों की संख्या 1063 है जिसमें से 1039 ग्राम परम्परागत् स्त्रोत से तथा 24 ग्राम अपरम्परागत् स्त्रोत से विद्युतीकृत हैं। वर्तमान में कांकेर जिला अन्तर्गत 03 संचारण-संधारण संभाग क्रमशः कांकेर, भानुप्रतापपुर एवं पखांजूर संभाग का संचालन किया जा रहा है, जिसमें स्थापित 40 नग 33/11 केवी उपकेन्द्रों में स्थापित 78 नग पॉवर ट्रांसफार्मर जिसकी कुल क्षमता 297.30 एमवीए के माध्यम से 29982 कृषि पम्पों सहित 2,13,832 विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति प्रदाय किया जा रहा है।

कांकेर जिले में 04 नग 132/33 केवी अति उच्चदाब उपकेन्द्र क्रमशः (1) उपकेन्द्र कांकेर(2) उपकेन्द्र पुत्तरवाही (3)उपकेन्द्र जॅवरतरा(4)उपकेन्द्र पखांजूर में कुल 383 एमवीए क्षमता के पॉवर ट्रांसफार्मर स्थापित है, इसके अतिरिक्त ग्राम पाण्डरवाही में 220/132 अति उच्चदाब उपकेन्द्र स्वीकृत है जिसका कार्य प्रक्रियाधीन है।

कांकेर जिले में 13 करोड़ 05 लाख रु की लागत से 05 एमवीए क्षमता के 02 नग 33/11 केवी उपकेन्द्र क्रमशः मांण्डाभरी एवं एकतानगर में तथा 3.15 एमवीए क्षमता के 3 नग 33/11 केवी उपकेन्द्र क्रमशः करमोती, बैंजनपुरी एवं मरोदा में स्थापित करने के कार्य को स्वीकृति प्रदाय किया गया है , जिसका निविदा कार्य प्रकियाधीन हैं। इस कार्य से 18982 उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

ग्राम पटौद में 87 लाख 86 हजार रु की लागत से 33/11 केवी उपकेन्द्र में 3.15 एमवीए क्षमता का अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर स्थापित कर चार्ज किया गया है अब उपकेन्द्र की क्षमता 6.30 एमवीए हो गई है। इस कार्य से 2784 उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति होगी।

विकासखण्ड चारामा के ग्राम परसोदा में 35 लाख 38 हजार रु की लागत से 33/11 केवी उपकेन्द्र में 3.15 एमवीए के पॉवर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करते हुए 5 एमवीए क्षमता का नया पॉवर ट्रांसफार्मर चार्ज किया गया, जिससेक्षमता बढ़कर 8.15 एमवीए हो गई है। इस प्रकार 35 लाख 38 हजार की लागत से स्थापित नये 5.00 एमवीए के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर के उर्जीकरण से 1701 उपभोक्ताओं लाभान्वित होंगे।

कोयलीबेड़ा में 33/11 केवी उपकेन्द्र छोटेचेतिया, गोण्डाहुर कापसी एवं उदयपुर में 2 करोड 89 लाख रुपए की लागत पृथक-पृथक 3.15 एमवीए क्षमता का अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर स्थापित कर चार्ज किया गया, इस प्रकार चारों उपकेन्द्रों की क्षमता 33.35 एमवीए हो गई है, जिससे 6550 विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति होगी।

एक करोड़ 84 लाख रु की लागत से 132/33 केवी उपकेन्द्र नगरी (चमेदा) से 33/11 केवी उपकेन्द्र बेलरगोंव तक 17 किमी. नवीन 33 केवी लाइन की स्थापना कर 33/11 केवी उपकेन्द्र जामगॉव में डबल सप्लाई की व्यवस्था बहाल की गई है जिससे 2118 उपभोक्ताओं लाभान्वित होंगे।

इसी प्रकार 73 लाख 92 हजार रु की लागत से 132/33 केवी उपकेन्द्र जॅवरतरा से 33/11 केवी उपकेन्द्र कोरर तक 14 किमी. नवीन 33 केवी लाइन की स्थापित किया गया जिससे 4565 उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

विकासखण्ड चारामा के ग्राम हल्बा में 3 करोड 68 लाख रु की लागत से 33/11 केवी उपकेन्द्र की स्थापना की गई है। इस उपकेन्द्र में 3.15 एमवीए क्षमता का पॉवर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है तथा 03 नग 11 केवी फीडर निर्गमित है, जिससे 1898 उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति होगी। विकासखण्ड नरहरपुर के ग्राम जुनवानी में 3 करोड 49 लाख रु की लागत से 33/11 केवी उपकेन्द्र में 3.15 एमवीए क्षमता का पॉवर ट्रांसफार्मर चार्ज किया गया है तथा 03 नग 11 केवी फीडर निर्गमित है जिससे 2139 उपभोक्ताओं लाभान्वित होंगे।

कांकेर के ग्राम कृष्टिकुर में 2 करोड 26 लाख रु की लागत से 33/11 केवी उपकेन्द्र की स्थापना की गई है। इस उपकेन्द्र में 3.15 एमवीए क्षमता का पॉवर ट्रांसफार्मर तथा 3 नग 11 केवी फीडर निर्गमित है, जिससे 2955 उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति किया जा रहा है।

क्र.	विवरण	मार्च 2000	मार्च 2025
1	132/33 केवी उपकेन्द्र	0	04
2	33/11 केवी उपकेन्द्र	8	40
3	33 केवी लाइन	198.75 किमी	713.26 किमी
4	11 केवी लाइन	511.428 किमी	5634.37 किमी
5	निम्नदाब लाइन	1314.563 किमी	8173.43 किमी
6	वितरण ट्रांसफार्मर की संख्या	805 नग	8220 नग
7	घरेलु कनेक्शन	25906	105472
8	गैर घरेलु कनेक्शन	11757	12204
9	पंप उपभोक्ता	1321	29595
10	विद्युतीकृत मजराटोला की संख्या	2674	4006



कोरबा पश्चिम औषधालय

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के महत्वपूर्ण संयंत्र हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम की स्थापना के साथ यहां चिकित्सालय की भी स्थापना 21 जून 1983 में हुई। दो आवासीय क्वार्टरों के भीतर चिकित्सालय की शुरूआत की गई थी। चिकित्सालय का उद्देश्य संयंत्र में कार्यरत सभी कर्मियों एवं परिजनों को सुगमता से चिकित्सा का लाभ उपलब्ध करना था।

वर्ष 1993 में सुसज्जित अस्पताल की स्थापना हुई। नये परिसर और सुव्यवस्थित चिकित्सा सुविधा में साठ शैया, चौदह चिकित्सकों और नर्सिंग स्टॉफ, वार्ड आया, दो बड़े शल्य कक्ष एवं प्रसूति गृह आदि की व्यवस्था की गई। विद्युत गृह के अधिकारियों-कर्मचारियों व उनके आश्रितों के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल यहां के चिकित्सक और स्टॉफ द्वारा निष्ठा के साथ किए जाने से इस चिकित्सालय की विश्वसनीयता व प्रतिष्ठा भी निरंतर बढ़ी।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी के अंतर्गत संचालित सभी चिकित्सालयों में केवल यहां ही एकमात्र लघु शल्य चिकित्सा जैसे गांठ निकालना, घाव सिलना, कटे कान सिलना आदि कार्य संपादित किया जाता है। साथ ही डी. एन. सी एवं प्रसूति कार्य की चिकित्सा सुविधा यहां उपलब्ध है। रक्त परीक्षण, एक्स रे आदि की सुविधाओं के साथ फिजियोथेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आकस्मिक उपचार हेतु इमरजेन्सी वार्ड में चौबीस घंटे चिकित्सक व स्टॉफ उपस्थित रहते हैं। हार्ट अटैक, डायबिटीज, हायपरटेन्शन आदि की चिकित्सा यहां उपलब्ध है। पूर्ण गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा यहां उपलब्ध है। इसके अलावा यहां आई सी यू व बर्न यूनिट भी हैं ताकि पॉवर प्लांट की किसी भी आकस्मिक दुर्घटना में घायल कर्मियों को तुरंत उपलब्ध हो सके।

चिकित्सालय में वर्तमान में अति. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मंजुला साहू, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ श्वेतांबरी महंता, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ रेणु कौशिक, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रीति पूनम कुजूर, चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रवीण कुमार पटेल द्वारा चिकित्सालय को संचालित किया जाता है। इनमें से डॉ मंजुला साहू व डॉ प्रवीण कुमार पटेल ए. एफ आई एच ट्रेनिंग प्राप्त हैं और विद्युत गृह की ओर से ओ एच सी की कानूनी आवश्यकता को बखूबी पूरा करते हैं।

राज्य पॉवर कंपनी चिकित्साल्यों में यहां इकलौता ऐसा चिकित्साल्य है, जहां रक्त परीक्षण एक्सरे आदि की सुविधाओं के साथ फिजियोंथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। आकस्मिक उपचार हेतु इमरजेंसी वार्ड में चैबीस घंटे चिकित्सक व स्टॉफ उपस्थित रहते है। हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाइपरटेन्शन आदि का पूर्ण गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा यहां उपलब्ध है। आईसीयू व बर्न यूनिट भी है, ताकि पॉवर प्लांट किसी भी आकस्मिक दूघर्टना में सफल चिकित्सा हो सकें।

> “हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम परिसर में
>
> 
>
> स्थित यह चिकित्सालय यहां के कर्मियों की चिकित्सा सुविधायों का केन्द्र है साथ ही आस - पास की सघन बस्तियों के लियें भी चिकित्सा का सशक्त माध्यम है।दवाई वितरण केन्द्र ,इंजेक्शन कक्ष, पट्टी कक्ष आदि सुविधाओं से युक्त अस्पताल चिकित्सा का बड़ा केन्द्र है। मरीजों के लिए दो एम्बुलेंस चौबीसों घंटे उपलब्ध रहती हैं। समय - समय पर शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है।”
>
> **▪ डॉ मंजुला साहू**
> अति मुख्य चिकित्सा अधिकारी
> हसदेव ताप विद्युत गुह चिकित्सालय कोरबा पश्चिम



टिफिन लाने से राहत, कार्य स्थल पर पांच रुपए में भोजन

अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र परिसर मड़वा में

- ***शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना के जरिए श्रमिकों को सस्ता भोजन देने की साय सरकार की गारंटी***

अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र परिसर में एक शेड के किनारे दोपहर के एक बजे सैकड़ों की संख्या में श्रमिकों की भीड़ जुटी हुई हैं। यह भीड़ कतारबद्ध होकर बारी-बारी से पांच रुपए की पर्ची कटवाकर अपना भोजन लेने जा रही है। उनकी थाली में चावल, सब्जी, दाल, अचार और पापड़ परोस दिया जा रहा है। भोजन गरमागरम है। श्रमिकों को भोजन का स्वाद भी पसंद आ रहा है। वहां जुटे भानुप्रताप, बोधीराम, रमशिल्या, मेमबाई जैसे सैकड़ों श्रमिकों को हर रोज दोपहर का भरपेट भोजन यहां मिल रहा है, वह भी पांच रुपए में। ठीक सुना आपने। राज्य सरकार श्रमिकों के हित में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना चला रही है। इसमें श्रमिकों को पांच रुपए में भरपेट गरम भोजन दिया जा रहा है। श्रमिकों के हित में क्रियान्वयन एजेंसी को राज्य सरकार 55 रुपए अपनी ओर से प्रति श्रमिक अनुदान दे रही है। इस तरह 60 रुपए का भोजन श्रमिकों को केवल पांच रुपए में दिया जा रहा है।

प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की यह महत्वाकांक्षी योजना है। राज्य सरकार ने इस योजना का शुभारंभ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया है। अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र में संचालित इस योजना का शुभारंभ वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी के हाथों किया गया है। इस अवसर पर वित्तमंत्री ने श्रमिकों से बातचीत कर योजना के लाभ के बारे में जाना। बातचीत में श्रमिकों ने इस योजना की भूरी.भूरी प्रशंसा की है।

हर रोज 450 श्रमिक योजना का उठा रहे हैं लाभ

विद्युत संयंत्र के कल्याण अधिकारी श्री राजेंद्र सिंह टेकाम ने बताया कि मड़वा विद्युत संयंत्र में रविवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन श्रमिकों को पांच रुपए में गरमागरम भोजन परोसा जा रहा है। हर रोज 350 से 450 श्रमिक दोपहर का भोजन लेने पहुंच रहे हैं। श्री टेकाम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ समकालीन निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल का गठन किया गया है। मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कारखाने एवं स्थापनाओं एवं उनमें कार्यरत श्रमिकों से अभिदाय प्राप्त किया जाता है। प्राप्त अभिदाय एवं शासन द्वारा दी गई सहायता राशि से संगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए शासन योजनाएं संचालित करती हैं। इसी के तहत शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना के जरिए पांच रुपए में गरम भोजन श्रमिकों को दिया जा रहा है।

योजना की खूबी, श्रमिकों की जुबानी

- हमन अब टिफिन नई लान, अब इंहे हमन भात दार सब्जी खा लेत हंन।
  - रमशिल्या यादव, ठेका श्रमिक



- खाना गरम मिलत हे पांच रूपिया म, अउ का चाही। अब हमन के पइसा भी बाचत हे। **-मेम बाई महंत, ठेका श्रमिक**
- दाल-भात के संग रोज आनीबानी साग मिलत हे। कभु राजमा-आलू, कभू चना-आलू, कभू भाटा-आलू। संगेसंग पापड़ अउ अचार भी रइथे। हमन अब टिफिन बनाय के झंझट ले मुक्ति पा गेहन।

- भानुप्रताप कश्यपए ठेका श्रमिक।

- सरकार के ये योजना ह हमर बर आय। ऐखर ले हमन ल मदद मिलत हे। साय सरकार ल हमन जोहार करत हन। बड़ सुध्धर योजना हे काम करइया मन बा।

- बोधीराम पटेल, ठेका श्रमिक।

▪ बसंत शाहजीत,
प्रकाशन अधिकारी, HTPS, कोरबा पश्चिम



मड़वा संयंत्र से 1100 श्रमिकों का श्रम कल्याण मंडल में है पंजीयन- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी में केवल अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र में यह योजना संचालित है। इसके संचालन के लिए श्रम पदाधिकारियों से समन्वय बनाकर सरकार की इस योजना का शुभारंभ कराया गया है। इससे श्रमिकों को बड़ा लाभ मिल रहा है। श्रम कल्याण मंडल में विद्युत गृह के 1100 श्रमिक पंजीबद्ध हैं।

▪ एचएन कोसरिया
मुख्य अभियंता ABVTPS, मड़वा

...इसलिए मिला राज्य स्तरीय सम्मान

नमिता विभा लकड़ा
कार्यपालन अभियंता
राज्य भार प्रेषण केन्द्र,
सीएसपीटीसीएल, रायपुर



मैं वर्ष 2007 से 2013 तक सिटी डिविजन (पूर्व) रायपुर, सीएसपीडीसीएल में कनिष्ठ अभियंता के पद पदस्थ रही । वर्ष 2013 से 2019 तक सहायक अभियंता एवं 2019 से वर्तमान में कार्यपालन अभियंता के पद पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र के "डेटा अनुभाग''में कार्यरत हूँ।

राज्य भार प्रेषण केन्द्र के डेटा अनुभाग में परिचालन रिपोर्ट की तैयारी, संकलन, सत्यापन और समन्वय गतिविधियों से संबंधित कार्य किया जाता है, जिसमें मूल रूप से श्रमसाध्य मैनुएल डेटा संकलन शामिल है।

राज्य भार प्रेषण केन्द्र के अंतर्गत ऑफलाइन डेटा संकलन और इसके साझाकरण और प्रस्तुतीकरण से संबंधित कुछ कार्यों को निम्नानुसार दर्शाया जा रहा है, जिसे राज्य स्तर पर तैयार किया जाता है।

400 केवी की ट्रांसमिशन लाइनों/तत्वों, सीएसपीजीसीएल उत्पादन इकाइयों के लिए एओएच/सीओएच, अंतर-क्षेत्रीय, अंतर-राज्यीय लाइनों एवं पीजीसीआईएल से कनेक्टिविटी वाली लाइनों के लिए प्लान्ड और पोस्ट ओसीसी आउटेज के लिए सहमति लेने के लिए डब्ल्यूआरपीसी, डब्ल्यूआरएलडीसी, सीएसपीटीसीएल और सीएसपीजीसीएल के बीच ''आउटेज समन्वयक'' के कार्य किये जाते है। अनिर्धारित लोड शेडिंग के संबंध में डेटा का संकलन और इसे सीएसईआरसी, डब्ल्यूआरपीसी, डिस्ट्रीब्यूशन के विभागों को प्रस्तुत कर भार प्रेषण केन्द्र के वेबपोर्टल में इसका अपडेशन किया जाता है। राज्यस्तर पर लोड जेनरेशन बैलेंस रिपोर्ट तैयार कर इसे डब्ल्यूआरपीसी को प्रस्तुत कर इससे संबंधित विभिन्न बैठकों में भाग लेना, इनपुट डेटा का संकलन एवं सत्यापन कर ट्रांसमिशन सिस्टम उपलब्धता फैक्टर (टीएसएएफ) की गणना करना, आईएसटीएस शुल्कों और हानियों से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में डेटा संकलन कर डेटा को एनएलडीसी और डब्ल्यूआरएलडीसी को प्रस्तुत करना, 132 केवी और उससे अधिक वोल्टेज के ''नए तत्वों की कमीशिनिंग विवरण'' से संबंधित डेटा का संकलन कर डब्ल्यूआरएलडीसी को प्रस्तुत करना, प्रारूप-29 में छत्तीसगढ़ राज्य की ऊर्जा आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट बनाकर सीईए और डब्ल्यूआरपीसी को प्रस्तुत करना, महानदी जल विवाद अधिकरण के लिए राज्य का पिछले 20 वर्षों का विद्युत संबंधित डेटा तैयार कर जनरेशन कंपनी के नोडल अधिकारी को प्रस्तुत किया गया, 19वें और 20वें इलेक्ट्रिक पॉवर सर्वेक्षण के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट से संबंधित डेटा तैयार किया गया, एयूएफएलएस से संबंधित डेटा का संग्रह एवं संकलन कर डब्ल्यूआरपीसी और डब्ल्यूआरएलडीसी को प्रस्तुत किया, 132 केवी और उससे अधिक वोल्टेज लेवल के सीपीपी डेटा को संकलन कर डब्ल्यूआरएलडीसी को प्रस्तुत किया, राज्य भार प्रेषण केन्द्र के संदर्भ में प्रशासकीय प्रतिवेदन संबंधित डेटा तैयार कर एचआर कार्यालय को प्रस्तुत किया और आवश्यकतानुसार डब्ल्यूआरपीसी द्वारा मांगी गयी लोकसभा और राज्यसभा प्रश्नोत्तर के संबंध में डेटा तैयार कर इसे समयानुसार प्रस्तुत किया जाता है, विधानसभा प्रश्नोत्तर डेटा तैयार कर संबंधित कार्यालयों में निश्चित समय पर प्रस्तुत करना, राज्य की मांग और ऊर्जा आपूर्ति के संबंध में डेटा तैयार करना। परिचालन डेटा का प्रबंधन कर आवश्यकता पड़ने पर संबंधित कार्यालयों/विभागों को इसे प्रस्तुत किया जाता है।वर्ष 2024 में जूरी सदस्यों के सामने चौथे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए छत्तीसगढ़ भार प्रेषण केंद्र की ओर से वर्चुअल मोड में प्रस्तुतिकरण तैयार कर प्रस्तुति दी गई। डब्ल्यूआरपीसी द्वारा संचालित संचालन और समन्वय समिति की मासिक बैठक में छत्तीसगढ़ भार प्रेषण केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए विभिन्न बैठकों में शामिल होना और इसके लिए मासिक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। संचालन और सुरक्षा के लिए उप-समिति का एजेंडा, प्रस्तुति और कार्यवृत्त तैयार किए गए। उपरोक्त कार्यों को बेहतर टीमवर्क और पूर्ण समर्पण के कारण इस कार्य को समय पर पूर्ण करने में सफलता मिली।

राज्य भार प्रेषण केन्द्र के सुचारू संचालन के लिए उपरोक्त डेटा का विनिमय सीएसपीसीएल के विभिन्न विभागों, डब्ल्यूआरएलडीसी, डब्ल्यूआरपीसी, एनएलडीसी, सीईए एवं एमओपी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

एचटीपीएस में आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन

हसदेव ताप विद्युत संयंत्र (एचटीपीएस) कोरबा पश्चिम के संयंत्र परिसर में 10 जून 2025 को प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षण एवं साइट डेमो का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय आपदा एवं बचाव दल (03बटालियन-एनडीआरएफ) मुंडली, कटक के उपनिरीक्षक श्री हेमराज पांडेय एवं उनकी टीम द्वारा दी गई। एनडीआरएफ की टीम द्वारा विद्युत संयंत्र के अधिकारी, कर्मचारी एवं श्रमिकों को आपदा के समय बचाव के तरीकों को सिखाया गया। इनमें प्रमुख रूप से सीपीआर, आपदा के समय घायल व्यक्तियों को सुरक्षित ढंग से उठाना एवं स्थानांतरित करना, रक्तस्राव रोकना, आपदा जैसे- सर्पदंश, बाढ़, चक्रवात एवं भूकंप के समय बरते जानी वाली सावधानियां एवं कार्य के बारे में विस्तार से बताया गया।

एनडीआरएफ टीम ने बच्चों के मामले में बाह्य वस्तु द्वारा सांस नली में रूकावट को दूर करने के उपाय को लाइव डेमो देकर बताया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य अभियंता श्री पीके श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में टरबाईन मेंटेनेंस डिवीजन-3 के अधीक्षण अभियंता श्री नरेंद्र उइके एवं अग्निशमन अधिकारी श्री जीपी पनरिया एवं उनकी टीम के संयोजन से आयोजित हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री एमके. गुप्ता, श्री पीके. स्वैन, श्री केएनबी. राव और वरिष्ठ मुख्य रसायनज्ञ श्री एके कुरनाल उपस्थित रहे।

132 केवी उपकेन्द्र मल्हार ऊर्जित

- **36 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत**
- **10 किलो मीटर की 132 केवी डबल सर्किट लाइन**



छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने बिलासपुर क्षेत्र को एक नई सौगात दी है। मल्हार में 132/33 केवी विद्युत उपकेन्द्र को प्रबंध निदेशक श्री आर के शुक्ला द्वारा 19 जून को उर्जाकृत किया गया। इस कार्य में 36 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत आई है। इसके साथ ही 10 किलो मीटर की 132 केवी डबल सर्किट लाइन भी ऊर्जाकृत की गई है। जिसको बनाने में 16.4 करोड रुपए खर्च किए गए है। इसका फायदा मस्तूरी क्षेत्र के 125 गांवों के 46 हजार उपभोक्ताओं को मिलेगा।

नवनिर्मित 132/33 केवी उपकेन्द्र मल्हार उप केन्द्र और 132 केवी डबल सर्किट लाइन का उर्जीकरण स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आरके शुक्ला द्वारा किया गया। इस उपकेन्द्र के निर्माण से मस्तुरी, पचपेड़ी, चिल्हाटी, केंवटाडीह और मल्हार उप केन्द्र में डबल सप्लाई की व्यवस्था हो जाएगी। साथ ही 33 केवी लाइन की लंबाई कम होने से ब्रेक डाउन में कमी आयेगी। साथ ही लो-वोल्टेज की समस्या का सामना नहीं करना पडेगा।

अब विद्युत उपभोक्ताओं को निरंतर एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति निर्बाध होगी। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक (लाइन) संजय पटेल, कार्यपालक निदेशक एके अंबस्ट, कार्यपालक निदेशक (ट्रांसमिशन) वीके दीक्षित, कार्यपालक निदेशक (परियोजना) ज्योति नन्नोरे, मुख्य अभियंता (सिविल) संजय तिवारी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता एसके दुबे, अधीक्षण अभियंता गौतम केनार, व्हीबीएस कंवर, पुष्पा पिल्लई, केके यादव, पीएस नेताम, सुरेश जांगडे, कार्यपालन अभियंता जीआर जायसवाल, सपथ खान, तामेश्वर सिंह, जेएल उरांव, बरखा दुबे, एस. घोष, सहायक अभियंता गजेन्द्र सोनी, वर्षा कुर्रे, बजरंग विश्वकर्मा, आकाश सिन्हा, मोहन देवांगन एवं पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

220 केवी उपकेन्द्र भिलाई में 2 नए फीडर बे ऊर्जीकृत

भिलाई खेदामारा 400 केवी अति उच्चदाब विद्युत उपकेन्द्र से 220 केवी में 2 फीडर बे को प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी श्री आर.के. शुक्ला द्वारा 21 मई को ऊर्जीकृत किया गया। पूर्व में 400 केवी खेदामारा उपकेन्द्र से 220 केवी लाइनों से विद्युत आपूर्ति की जा रही थी। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी द्वारा अपने पारेषण तंत्र को मजबूत करने की दिशा में इस कार्य को पूर्ण किया गया। 400 केवी अति उच्चदाब विद्युत उपकेन्द्र खेदामारा से 220 केवी उपकेन्द्र भिलाई में पहले ही 2 लाइनों से विद्युत आपूर्ति की जा रही थी। श्री शुक्ला द्वारा 2 अन्य फीडर बे को ऊर्जीकृत किया गया जिससे अब 220



केवी से कुल 4 लाइनों से विद्युत आपूर्ति की जाएगी। नई लाइन की लंबाई क्रमशः 12.72 किलोमीटर व 17.92 किलोमीटर है। यह कार्य अति उच्चदाब निर्माण वृत्त के मार्गदर्शन में पूर्ण किया गया, जिसकी लागत 5 करोड़ रु. है। इस कार्य से दुर्ग, भिलाई क्षेत्र के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति होगी, इसके अलावा गुरूर और भाटापारा क्षेत्र को भी भिलाई उपकेन्द्र से विद्युत आपूर्ति होगी। इस कार्य से गर्मी के मौसम में किसानों एवं उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक लाइन श्री संजय पटेल, दुर्ग क्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री संजय खण्डेलवाल व अधीनस्थ अधिकारीगण श्री पीपी सिंह, श्री सुनील भूआर्य, श्रीमती पुष्पा पिल्लई तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

अनवरत विद्युत विकास

» भर्रीटोला, बालोद



बालोद जिला कलेक्टर श्रीमती दिव्या मिश्रा द्वारा भर्रीटोला वितरण केन्द्र के 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र में लो-वोल्टेज की शिकायत के निराकरण हेतु निर्देश दिया गया, जिसके परिपालन में मुख्य अभियंता दुर्ग श्री संजय खंडेलवाल द्वारा 22 मई को 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र भर्रीटोला में 3.15 एमवीए के पॉवर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करते हुये 5 एमवीए का नया पॉवर ट्रांसफार्मर चार्ज किया गया।

उपकेन्द्र की क्षमता 6.30 एमवीए से बढ़कर 8.15 एमवीए हो गई है। इस कार्य में रू. 46.63 लाख की लागत आई है। नये 5 एमवीए के पॉवर ट्रांसफार्मर से डौंडी सहित कुंजकन्हार, सुरडोंगर, लिमऊडीह, कुवागोंदी, कांडे, घोठिया, पटेली, पचेड़ा, ढोरीठेमा, मडियाकट्टा, पेण्ड्री, ओडगांव, वनपण्डेल, उरझे, लैनकसा, मरकाटोला(एस) खुर्सीतिकुर, भर्रीटोला, अवारी, गुदुम, बम्हनी एवं छिंदगांव के लगभग 18 ग्रामों के 3000 उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति का लाभ मिलेगा।

इस अवसर पर श्री एस.के.बंड, श्री प्रफुल्ल पलसोलकर, श्री धर्मेन्द्र भारती, श्री आर.सी.साहू, श्री डी.के.साहू, श्री टी.एस.भाटिया उपस्थित थे।

» ग्राम नवागांव

ग्राम नवागांव कला में नये 33/11 केवी



विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण उपरांत मुख्य अभियंता श्री संजय खंडेलवाल ने 30 मार्च को इस उपकेन्द्र को ऊर्जीकृत किया । इस कार्य मे 02 करोड़ 26 लाख रुपये की लागत से जिससे 5 गांवों के लगभग 1214 उपभोक्ताओं एवं किसानों को बिजली की आपूर्ति होगी।

श्री खंडेलवाल ने बताया कि नये उपकेन्द्र में तीन नये फीडर बनाये गये हैं जिनमें से 11 केवी नवागांव कला बस्ती फीडर 21 किलोमीटर लंबी है। इस फीडर से ग्राम नवागांव कला, जेवरा एवं मटिया के उपभोक्ता लाभान्वित होंगे । नवागांव कला पंप फीडर जो 13 किलोमीटर लंबी है, ग्राम नवागांव, जेवरा एवं मटिया के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिलेगी। धरकपुर पंप फीडर की लंबाई 09 किलोमीटर है जिससे ग्राम धरकपुर एवं कांपा के किसानों को लाभ मिलेगा। इस कार्य के लिए अधीक्षण अभियंता श्री सलिल कुमार खरे, कार्यपालन अभियंता श्री मनीश षुक्ला, श्री मोहम्मद जलालुद्दीन एवं श्री पी.के.पलसोकर सहित उनकी पूरी टीम को बधाई दी गई।

» अम्बागढ़ चौकी/मोहला

अम्बागढ़ चौकी, बांधाबाजार, आमाटोला एवं चिल्हाटी क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में निर्बाध व गुणावत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एकटकन्हार स्थित 132 केवी उच्चदाब उपकेन्द्र में 29 किमी नई 33 केवी लाइन का निर्माण किया गया। जिसे कार्यपालक निदेशक श्री शिरीष सेलट द्वारा 13 मई को उर्जीकृत किया गया। इस कार्य में 2 करोड़ रूपये की लागत आई है।

अब अम्बागढ़ चौकी, चिल्हाटी क्षेत्र के लिए विद्युत प्रदाय व्यवस्था मोहला के एकटकन्हार स्थित 132/33 केवी उच्चदाब उपकेन्द्र एवं अमलीडीह डोंगरगांव 132/33 केवी उच्चदाब उपकेन्द्र दोनों से पूरी होगी । जिससें अम्बागढ़ चौकी, बांधाबाजार, आमाटोला एवं चिल्हाटी क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों के लगभग 25 हजार उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा।



» मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी



जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी के घोर नक्सल प्रभावित एवं अत्यंत सघन वनों से घिरे 17 वनग्रामों कातुलझोरा, कट्टापार, बोदरा, बुकमरका, संबलपुर, गट्टेगहन, पुगदा, आमाकोड़ो, पीटेमेटा, टाटेकसा, कुंदलकाल, रायमनहोरा, नैनगुड़ा, मेटातोडके, कोहकाटोला, एडसमेटा एवं कुंजकन्हार में विद्युतीकरण के कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कार्यपालक निदेशक श्री शिरीष सेलट द्वारा ग्राम टाटेकसा में स्थापित 25 केवी के वितरण ट्रांसफार्मर को 14 मई को चार्ज किया गया।

इन ग्रामों में 540 परिवार निवासरत है, जिसमें से 275 परिवारों को कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। उक्त ग्रामों के विद्युतीकरण में कुल 45 कि.मी.

11 केवी लाइन, 87 नग निम्नदाब पोल विस्तार एवं 17 नग 25 केवी का ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। इन ग्रामों में 11 केवी लाइनों को खिचनें के लिए पहले वन विभाग से एनओसी लेना पड़ा। उसके बाद मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ की राशि की प्राक्कलन स्वीकृत कर विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया गया। वनग्रामों के लोगो ने पहली बार अपने गांव में पांरपरिक बिजली की रोशनी देखी। विद्युतीकरण का कार्य पूरा होने के बाद ग्रामीणों ने खुशी में हर्षोल्लास के साथ पटाखे फोड़े।

इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता श्री शंकेश्वर कंवर, कार्यपालन अभियंता श्री मुकेश कुमार साहू, श्री अनिल रामटेके सहायक अभियंता श्री शिरीष मिलिंद सहित ग्रामीणजन मौजूद रहे।

» मोहला



मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतीकरण योजना के तहत जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी के लिए 07 करोड़ 33 लाख रूपये की राशि स्वीकृत कर 1280 परिवारों को बिजली की सुविधा प्रदान की गई। राजनांदगांव क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक श्री शिरीष सेलट ने बताया कि इन ग्रामों में 11 केवी लाइनों को बिछानें के लिए वन विभाग से एनओसी लेना पड़ा। सुदूर, सघन वनों में बसे एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 100 ग्रामों के पारा, मोहल्ला एवं मजराटोलाओं में कुल 1280 परिवार निवासरत है, जिसमें 1125 परिवारों को कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। विद्युतीकरण में कुल 65 कि.मी. 11 केवी लाइन 275 नग निम्नदाब पोल विस्तार एवं 60 नग 25 केवी का ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है।

जिससे ग्राम हुरेली, कुन्जकन्हार, मरकाटोला, रेंगाटोला, आलकन्हार, लमटी मुन्देली, अमापायली, भुरसा, छुरिया, एकटकन्हार, सुवरबोड़, कोतरी, कोरकोट्टी, अडमा, माझीटोला, मालडोंगरी, चिल्हाटी, जादूटोला, मरारटोला, सरखेड़ा, जामड़ी, तोलुम, नवागांव, हलोरा, मरापीटोला, तरेगांव, ख्वासफड़की, बसेली, गोटुलमुड़ा, मिचगांव, मरकेली, माल्हर, खैरकट्टा, कांडे, खुर्सेखुर्द, सरोली, पुन्गारीटोला, षेरपार, ईरागांव, नेड़गांव, मेढ़ा, कट्टापार, ककईपार, दोरदे, अलकन्हार, कटेंगाटोला, सुवरपाल, कुम्हली, तुमड़ीकसा, रानवाही, रेंगाकठेरा, कोरवा, डोकलाकोंडे, मोहला, नेतामटोला, नातीपार, कुडेंराटोला, कुम्हारी, दनगढ़, जिर्राटोला, पदगोंदी, बगनरा, बिहरीकला, कौड़ीकसा, मार्री, एहोड़ा, चांवरगांव, पटेली, मंडावीटोला, मुरेर, नरसूटोला, तोयागोंदी, पाटनवाडवी,वासड़ी, पटेली, गुन्डरदेही, पंडरीतरई, आतरगांव, बुटाकसा, परसाटोला, तुमड़ीकसा, घोरदा, माहुद, पांगरी, केसरीटोला, नेतामटोला, करमतरा, हांडीटोला, सिंगरायटोला, ओटेबांधा, हाथीकन्हार, पेन्दलकुही, अडमागोंदी, तिरपेमेटा, रंगकठेरा, केकतीटोला एवं छछानपहरी के पारा, मोहल्ला एवं मजराटोलाओं के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

» डोंगरगढ़



ग्राम कन्हारडबरी में 2 करोड़ 92 लाख रु की लागत से नवनिर्मित 33/11 केवी उपकेन्द्र को कार्यपालक निदेशक श्री शिरीष सेलट द्वारा 22 अप्रैल को ऊर्जीकृत किया गया। इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता श्री एस.कंवर, कार्यपालन अभियंता श्री एन.के. साहू, श्री एम. के. साहू, सहायक अभियंता श्री दिलीप सोनी, श्री राजेन्द्र साहू, कनिष्ठ अभियंता श्री कमलेश सोनवानी सहित पूरी टीम मौजूद रहे। इस उपकेन्द्र में स्थापित 3.15 एमवीए के पॉवर ट्रांसफार्मर से निकलने वाले 11 केवी के तीनों फीडरों यथा कन्हारडबरी, कसारी एवं आलीवारा के माध्यम से 08 ग्रामों के 1625 कृषक एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की जायेगी।

» मानुपर



मानपुर के 33/11 केवी उपकेन्द्र में 1.60 एमवीए के पॉवर ट्रांसफार्मर का क्षमता वृद्धि करते हुए 3.15 एमवीए का नया पॉवर ट्रांसफार्मर स्थापित कर 23 अप्रैल को चार्ज किया गया। इस प्रकार मानपुर उपकेन्द्र की क्षमता 4.75 एमवीए से बढ़कर 6.30 एमवीए हो गया है।

इस कार्य में 1 करोड़ 35 लाख रूपये की लागत आई है जिससे स्थापित नये 3.15 एमवीए का अतिक्ति पॉवर ट्रांसफार्मर के ऊर्जीकरण से वनांचल मानपुर क्षेत्र के 32 ग्रामों के 4050 उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति होगी। कार्यपालक निदेशक श्री शिरीष सेलट एवं अधीक्षण अभियंता श्री एस. कंवर ने कार्यपालन अभियंता, श्री ए.के. रामटेके, सहायक अभियंता श्री शिरीष मिलिंद, श्री एस.के. ठाकुर, श्री आर.पी. ठाकुर, कनिष्ठ अभियंता सुश्री भावना मंडावी की सराहना की है।

» कुमरदा

डोंगरगांव उपसंभाग के ग्राम कुमरदा में कार्यपालक निदेशक श्री



शिरीष सेलट द्वारा 3.15 एमवीए का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित कर 25 मई को ऊर्जीकृत किया गया। इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता राजनांदगांव वृत्त श्री एस. कंवर, कार्यपालन अभियंता, श्री बी.के. उइके, श्री एम.के. साहू, श्री एडी. टण्डन, सहायक अभियंता श्री आरपी ठाकुर, श्री राजेन्द्र साहू, कनिष्ठ अभियंता सुश्री धनेश्वरी चन्द्रवंशी उपस्थित थे।

कुमरदा उपकेन्द्र में 1 करोड़ 35 लाख रूपये की लागत से स्थापित अतिरिक्त 3.15 एमवीए का पॉवर ट्रांसफार्मर के ऊर्जीकरण से ग्राम लाटमेटा, चारभांटा, मोतीपुर, कुलहाड़ी, नादिया एवं घुपसाल के 1150 उपभोक्ताओं को फायदा होगा। अब कुमरदा उपकेन्द्र की क्षमता 6.60 एमवीए से बढ़कर 8.15 एमवीए हो गया है।

» कौड़ीकसा



नवीन जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी के ग्राम कौड़ीकसा में 33/11 केवी उपकेन्द्र में 3.15 एमवीए के अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर को कार्यपालक निदेशक श्री शिरीष सेलट ने 26 मई को ऊर्जीकृत किया। इस अवसर पर श्री एस. कंवर, कार्यपालन अभियंता श्री ए.के. रामटेके, श्री एम.के. साहू, श्री ए.डी. टण्डन, सहायक अभियंता श्री आर पी ठाकुर, श्री भारत कुर्रे उपस्थित थे। कौड़ीकसा उपकेन्द्र की पॉवर क्षमता 05 एमवीए से बढ़कर 8.15 एमवीए हो गई है।

इस उपकेन्द्र में 1 करोड़ 28 लाख रूपये की लागत से स्थापित नये 3.15 एमवीए का अतिक्ति पॉवर ट्रांसफार्मर के ऊर्जीकरण से 32 ग्राम कौड़ीकसा, मेटेपार, बिहरीकला, गौलिटोली, घोरदा, तारमटोला, नेतामटोला, कुंवारदल्ली, देववाड़वाी, पटेली, कुदुरघोड़ा, डोड़के, चमरूटोला, बगनारा, माहुद मचांदुर, गोर्राटोला, देवरसुर, मुंगेषीटोला, भर्रीटोला, भगवानटोला, निचेकोहड़ो, अरजकुंड, तुमड़ीकसा, भुरभुसी, बुटाकसा, घावड़ेटोला, मोहड़, पण्डरीतराई, गोपलिनचुवा, दनगढ़, खुर्सीटिकुल एवं आड़ेझर के 13445 उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति होगी।

» दल्ली राजहरा



बालोद जिले में स्थित दल्ली राजहरा टाउन वितरण केंद्र के अंतर्गत 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र चिखलाकसा में 75 लाख रुपए की लागत से 3.15 एमवीए का अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर लगाकर 2 जून को उर्जीकृत किया गया, जिससे उपकेन्द्र की क्षमता बढ़कर 13.15 एमवीए हो गई है। इस कार्य से लगभग 3000 उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति होगी।

श्री एस.के. बंड ने बताया कि उपकेन्द्र में अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर लगने से चिखलाकसा, मथुरा नगर, निर्मला स्कूल क्षेत्र, ओड़िया पारा, मच्छी मार्केट, ट्यूबलर सेट, पटेल कॉलोनी, श्रमवीर चौक, बस स्टैंड, सुभाश चौक, एमबीपी सेंटर एरिया के उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर मुख्य अभियंता श्री संजय खंडेलवाल ने श्री सलिल कुमार खरे, ,श्री डी.के. भारती ,श्री पी.के.पलसोकर और उनकी पूरी टीम को बधाई दी।

» दुर्ग

दुर्ग क्षेत्र के छावनी जोन अंतर्गत स्थित 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र घासीदास नगर में 96 लाख 62 हजार रुपए की लागत से 05 एमवीए के अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर लगाकर 4 जून को उर्जीकृत किया गया, जिससे उपकेन्द्र की क्षमता बढ़कर 10 एमवीए हो गई है। उक्त कार्य के होने से उपकेन्द्र के अंतर्गत लगभग 1900 उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति होगी।

इस अवसर पर मुख्य अभियंता श्री संजय खंडेलवाल, श्री डी.के.भारती एवं श्री एस.के. राय और उनकी पूरी टीम उपस्थित थे।

» झाल



दुर्ग क्षेत्र संभाग बेमेतरा के अंतर्गत स्थित 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र झाल में 05 एमवीए का अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर लगाकर 04 जून को उर्जीकृत किया गया, उपकेन्द्र की क्षमता बढ़कर 15 एमवीए हो गई । जिससे लगभग 1955 उपभोक्ताओं एवं किसानों को विद्युत आपूर्ति मिलेगी। इस कार्य में 97 लाख 72 हजार रुपए की लागत आई।



इस अवसर पर मुख्य अभियंता श्री संजय खंडेलवाल अधीक्षण अभियंता वृत्त श्री सलिल कुमार खरे, कार्यपालन अभियंता परियोजना श्री मोहम्मद जलालुद्दीन, कार्यपालन अभियंता एसटीएम श्री पी.के. पलसोकर तथा उनकी पूरी टीम उपस्थित थे।



गुंजेश तामले

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बिलासपुर में उच्च दाब सुधार निर्माण, नगर संभाग 2, (पश्चिम) में पदस्थ श्री जे आर तामले, कनिष्ठ अभियंता के सुपुत्र गुंजेश तामले का जेईई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक ओपन में 4552 प्राप्त किये, वहीं जेईई मैंस प्रथम में 99.67 परसेंटाइल के साथ चयन हुआ था एवं जेईई मैंस द्वितीय में 99.42 परसेंटाइल के साथ चयन हुआ था। वे कृष्णा पब्लिक स्कूल कोनी बिलासपुर का विद्यार्थी है।



आशना दिल्लीवार

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कार्यापालन अभियंता के पद पर कार्यरत श्रीमती संध्या दिल्लीवार एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में निदेशक श्री कमलेश दिल्लीवार की सुपुत्री सुश्री आशना दिल्लीवार ने राज्य शासन द्वारा आयोजित राजिम कल्प कुंभ एवं भोरमदेव महोत्सव 2025 में विविध सांस्कृतिक आध्यात्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में शास्त्रीय कथक नृत्य की गरिमामय प्रस्तुति दी।उन्होंने इस कार्यक्रम में शिव परन, शिव वंदना, तराना, तत्कार के प्रकार एवं अंत में दक्ष यज्ञ की कथा का मंत्र पर मनमोहक प्रदर्शन किया।



रौनक कुलदीप

नेपाल की युवा एवं खेल मंत्रालय और नेपाल कराटे फेडरेशन द्वारा आयोजित लुम्बिनी इंटरनेशनल कराते चैम्पियनशिप 2025 में स्पर्धा में सब जूनियर, जूनियर अंडर 18, सीनियर वर्गों में महिला एवं पुरूषों के व्यक्तिगत और टीम काता की विभिन्न किलोग्राम वर्गों में प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान के एक हजार से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जिसमे छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांशमिशन कंपनी में कार्यरत श्रीमती पूर्णिमा कुलदीप उपमहाप्रबंधक मानव संसाधन रायपुर के सुपुत्र रौनक कुलदीप को इस स्पर्धा में सब जूनियर 14-15 वर्ष के अंडर 65 किलोग्राम वर्ग में व्यक्तिगत काता में स्वर्ण पदक एवं कुमिते (फाइट) स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया।



ओजस भारती

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कम्पनी के संचार उत्पादन मुख्यालय रायपुर में पदस्थ अधीक्षण अभियंता, श्रीमती कविता योगेन्द्र भारती के सुपुत्र ओजस भारती ने लुम्बिनी इंटरनेशनल कराते चैम्पियनशिप 2025 में 25 किलो भार अंतर्गत ''फाइट'' में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक अर्जित किया और ''काता'' में भी प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक का विजेता बना।



अर्चित श्रीवास्तव

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) कार्यालय में पदस्थ प्रबंधक श्री विकास श्रीवास्तव के सुपुत्र अर्चित ने लुम्बिनी इंटरनेशनल कराते चैम्पियनशिप 2025 के सब जूनियर ग्रुप के 20 किलोग्राम वर्ग में व्यक्तिगत काता और कुमिते (फाइट) स्पर्धा में रजत पदक जीते हैं।



अंशुमन ठाकुर

अधीक्षण अभियंता रायपुर सिटी सर्किल दो, श्री महेश ठाकुर एवं ईडी (संचा. एवं संधा.) में कार्यपालन अभियंता श्रीमती कंचन ठाकुर के सुपुत्र अंशुमन ने बीसीसीआई की राजसिंह डूंगरपुर अंडर -14 टूर्नामेंट में कप्तानी करते हुए टीम का नेतृत्व किया। प्रतियोगिता में उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन को देखते हुए अंडर -16 टीम के ट्रायल के लिए चयन किया गया है। अंशुमन छत्तीसगढ क्रिकेट संघ के अंडर-14 टीम का भी हिस्सा हैं साथ ही वे स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। 9 वीं कक्षा के छात्र अंशुमन के पिता श्री महेश ठाकुर पॉवर कंपनी की क्रिकेट टीम का राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में नेतृत्व कर चुके हैं। उनकी माता श्रीमती कंचन भी विदयुत मंडल खेलों में कैरम प्रतियोगिता में पॉवर कंपनी का प्रतिनिधित्व करती हैं।

अति उच्च दाब उपकेन्द्रों के लिये कनिष्ठ अभियंता के पद स्वीकृत

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने नवनिर्मित 132 केवी अति उच्च दाब उपकेन्द्रों (एक्ट्रा हाई वोल्ट सब स्टेशन) में नए पदों की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत नौ कनिष्ठ अभियंताओं के पद स्वीकृत किये गए हैं। वे इन उपकेन्द्रों में ऑपरेशन एवं मेन्टेनेंस का कार्य संपादन करेंगे। पॉवर कंपनी के अधिशासी निकाय की 117वीं बैठक में इसका निर्णय लिया गया, जिसके बाद ट्रांसमिशन कंपनी के मानव संसाधन विभाग ने पद संरचना का आदेश जारी कर दिया है। इसमें 132 केवी सबस्टेशन छापनी, गुल्लु (आरंग), बैजलपुर, टेमरी, जनकपुर, मेटल पार्क, मल्हार (मस्तुरी), जामगांव व महराजपुर में नौ कनिष्ठ अभियंता के पद स्वीकृत किये गए हैं। इनके अलावा क्षेत्रीय भंडार गृह भिलाई व बिलासपुर में भी कनिष्ठ अभियंता के एक- एक पद स्वीकृत किये गए हैं। जल्द ही यहां पदस्थापना की जाएगी।

श्री वीरेन्द्र कुमार दीक्षित

कार्यपालक निदेशक (ट्रांसमिशन)

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी



छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी मे कार्यपालक निदेशक ट्रांसमिशन के पद पर पदस्थ श्री वीरेन्द्र कुमार दीक्षित का जन्म 30 सितम्बर 1964 को कटनी, मध्यप्रदेश में हुआ। पिता का नाम श्री क्रांति कुमार दीक्षित एवं माता का नाम श्रीमती शंकुतला देवी दीक्षित है। उन्होंने हायर सेकेंडरी की परीक्षा विद्युत गृह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ,कोरबा से वर्ष 1980 मे उत्तीर्ण की। वर्ष 1986 में शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय बिलासपुर से बीई इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर कोर्स की उपाधि ली।

श्री दीक्षित की सेवायात्रा वर्ष 1988 में स्नातक प्रशिक्षु के रूप में शुरू हुई। इस दौरान श्री दीक्षित E.S.CI हैदराबद से अति उच्च दाब लाइनों एवं उपकेन्द्रों की सुरक्षा एवं अर्थिग संबंधी एवं CIRE हैदाराबाद से ग्रामीण विद्युतीकरण, अक्षय ऊर्जा एवं राजस्व प्रबंधन जैसे कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त किये। वर्ष 1989 मे सहायक अभियंता के नियमित पद पर एसटीआरई निर्माण उपसंभाग ,दर्री कोरबा मे पदस्थ हुये जहां ग्रामीण विद्युतीकरण के अतिरिक्त एचटीपीएस के 33/04 केवी के 12 उपकेन्द्रों के डुप्लीकेटिंग कोल कन्वेयर का निर्माण कार्य एवं कमीशनिंग का कार्य पूर्ण कराया। इसी पद पर रहते हुए 400 केवी से 132 केवी लाइनों के सुधार एवं संधारण कार्य तथा अति उच्च दाब उपभोक्ता विशेषतः मोदी, अंबूजा, सेंचुरी, टिस्को सोनाडीह, ग्रासिम, एल एंड टी, रेमंड जैसे अतिउच्चदाब उपभोक्ताओं को सेवाएं दी। राजस्व के कार्यों का कार्य निष्पादन ,निम्नदाब उपभोक्तओं से संबंधित कार्य, विधान सभा से जुड़े कार्यों को सफलतापूर्वक संपादित किया। तत्कालीन बिलासपुर वृत्त के अंतर्गत रायगढ़, जांजगीर, कोरबा आदि क्षेत्र में सीमित संसाधनों में समय पर कार्य पूर्ण करने का कीर्तिमान बनाया।

वर्ष 2006 में कार्यपालन अभियंता के पद पर पदोन्नति उपरान्त एसटीएम संभाग बिलासपुर में पदस्थ किये गए। निविदा कार्य, लाइन एवं उपकेन्द्र से संबंधित टर्न की संबंधित कार्य, उपभोक्ताओं के इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटरों को इलेक्ट्रॉनिक मीटर से बदलने का कार्य, 100 : आर.टी.यू. कमीशनिंग का कार्य, नये कॉरीडोर एवं एनएचएआई के कार्यों को गति दी एवं निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण किये।

वर्ष 2017 में अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति प्राप्त कर अ.उ.दा. (संधारण.) संभाग, कोरबा में लगभग 4 माह पदस्थ रहे। अधीक्षण अभियंता संचारण/संधारण भिलाई में रहते हुए दो 132 केवी एवं एक 220 केवी गेंदपुर (कवर्धा) निर्माणाधीन उपकेन्द्र के नोडल अधिकारी के तौर पर उपकेन्द्र चार्ज करवाया एवं कुल 9 में से 9 अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों का कार्य पूर्ण करवाया।गुरूर का 160 एमवीए ट्रांसफार्मर जो विगत एक वर्षों से लंबित था, जिसमें काफी संख्या में बे शिफ्टिंग का कार्य शामिल था उसे दो माह के भीतर चार्ज करवाया। कुसमुंडा उपकेन्द्र की लाइन का कार्य जो कि फॉरेस्ट क्लीयरेंस की वजह से रूका था, की वैकल्पिक व्यवस्था कर दूसरा सर्किट उपलब्ध करवाया, जिससे एस.ई.सी.एल. का खनन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। बिलासपुर तिफरा में दूसरे फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य दो ई.एच.वी. लाइन 132 केवी डबल सर्किट बिलासपुर ट्रैक्सन एवं 132 केवी तिफरा से सिलपहरी लाइन में ओव्हर लोडिंग की वजह से शट-डाउन उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य बाधित था। श्री दीक्षित द्वारा सिलपहरी लाइन में विशेष व्यवस्था कर शट-डाउन प्रदान करवाया गया जिससे डबल ए.जी.टी. का कार्य पूर्ण कराया गया। यह कार्य उच्चन्यायालय की 3 दिनों की छुट्टी के दौरान लगातार बारिश एवं कीचड़ में रेन कोट पहनाकर पूर्ण किया गया जिसके कारण तिफरा के ट्रैफिक जाम से आम जनता को राहत मिली। इस बाबत् तत्कालीन कलेक्टर बिलासपुर के द्वारा प्रसन्नता एवं प्रशंसा की गयी, वस्तुतः यह एक अद्वितीय कार्य था। बिलासपुर में कानन पेंडरी के पास गिरे टॉवर जिससे कोटा-तखतपुर क्षेत्र का विद्युत आपूर्ति बाधित था, जिसे 24 घंटे के भीतर टॉवर को खड़ा कर विद्युत आपूर्ति चालू की गयी जिसकी प्रशंसा तत्कालीन अध्यक्ष ने भी की। द्वितीय सर्किटिंग जशपुर-पत्थलगांव एवं विश्रामपुर, बलरामपुर उपकेन्द्र से होने वाली विद्युत आपूर्ति का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। बलरामपुर की विद्युत आपूर्ति भी सिंगल सर्किट रेडियल फीडर से होती प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजे गये जिसमें दो लाइनों का कार्य पूर्ण हो चुका है, तीसरे तखतपुर का कार्य प्रगति पर है। 100 मेगावॉट पॉवर हाउस स्विच यार्ड जो कि ट्रांसमिशन कंपनी को हस्तांतरित किया गया था का पुनर्निर्माण करवाया एवं जनरेशन कंपनी से पृथक कर ट्रांसमिशन कंपनी के नियंत्रण में लिये जाने का कार्य पूर्ण करवाया। रेलवे, एस.ई.सी.एल, एन.एच.ए.आई के तथा दो 132 केवी उपकेन्द्रों का निर्माण एवं कमीशनिंग का कार्य उदयपुर (अम्बिकापुर) एवं खरमोरा (कोरबा) का कार्य सफलतापूर्वक निष्पादित किया।

वर्ष 2022 में अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नत हो कर कार्यपालक निदेशक (सी एंड एल.एम.) कार्यालय मे पदस्थापना मिली। तदोपरान्त रायपुर कार्यालय में कई उपकेन्द्रों की टेस्टिंग/कमीशनिंग आदि का कार्य निष्पादित किया।

वर्ष 2024 में पदोन्नत हो मुख्य अभियंता (मा.सं.) ट्रांसमिशन कार्यालय में पदस्थ किये गये। इस दौरान श्री दीक्षित के मार्गदर्शन में गणतंत्र दिवस समारोह 2025 का सफल आयोजन कराया गया। तदपश्चात मुख्य अभियंता (ट्रांसमिशन) के रूप में पदोन्नति मिली। 400 केवी उपकेन्द्र, कुरूद से निकलने वाली 220 केवी राजिम-2 सर्किट की चार्जिंग, 400 केवी उपकेन्द्र, कुरूद के 315 एमवीए आई.सी.टी.-3 की चार्जिंग, 400 केवी उपकेन्द्र कुरूद से निकलने वाली 400 केवी लाइन धमधा-1 तथा धमधा-2 की चार्जिंग, 400 केवी उपकेन्द्र, खेदामारा से निकलने वाले 220 केवी बी.आर.एस.एस.-3 एवं बी.आर.एस.एस.-4 लाइन की चार्जिंग, 400 केवी उपकेन्द्र, जगदलपुर के 400 केवी. ठंले जैपुर-1 तथा जैपुर-2 की चार्जिंग, 400/220 केवी. उपकेन्द्र, धरदेही के निर्माण कार्य को पूर्ण करने का अथक प्रयास जारी है। वर्ष 2025 में कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नति पश्चात इसी कार्यालय में ही पदस्थ रहे। इस दौरान उपरोक्त कार्यों के साथ धरदेही 400 केवी उपकेन्द्र के निर्माण कार्य को गति दी, जो कि चार्जिग स्तर पर है ।

उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नमिता दीक्षित ने एमएससी प्राणीशास्त्र,पीजीडीसीए एव एमसीए की उपाधि अर्जित की है और एससीसीए बिलासपुर से सेवानिवृत्त हुई हैं। पुत्री रूचिका दीक्षित बीई (कम्यूनिकेशन) एवं एमटेक (वीएलएसआई) जबलपुर से करने उपरांत वर्तमान मे बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत है। पुत्र श्री रितिक दीक्षित बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर आईआईटी मुम्बई से ऑटोमोबाइल मे विशेष सर्टिफिकेट कोर्स करने उपरान्त पुणे की आईटी कंपनी में कार्यरत है।

श्री दीक्षित सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यो में भाग लेते रहते हैं। उन्हें तैराकी, पर्यटन एवं सायकिलिंग बेहद पसंद है। प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक चिकित्सा में अध्ययन एवं शोध पसंद है तथा सेवानिवृत्ति उपरांत प्राकृतिक खेती एवं प्राकृतिक स्वास्थ्य से लोगों को जागरूकता प्रदान करने का इरादा है।

श्री प्रवीण श्रीवास्तव

मुख्य अभियंता (उत्पादन)

हसदेव ताप विद्युत संयंत्र, कोरबा पश्चिम



श्री प्रवीण श्रीवास्तव का जन्म 15 अक्टूबर 1963 को कटनी (मप्र) में हुआ था। इनके पिताजी का नाम स्व. प्रभुलाल वर्मा एवं माताजी का नाम स्व श्रीमती एमके. वर्मा है। उनके पिताजी स्कूल में प्रिंसिपल रहे एवं माताजी गृहिणी रहीं। श्री श्रीवास्तव की स्कूली शिक्षा वर्ष 1980 में आर्डनेंस फैक्ट्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटनी से पूरी हुई । वर्ष 1985 में रायपुर स्थित शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय (अब एनआईटी) से बीई मैकेनिकल (ऑनर्स) की उपाधि प्राप्त की।

श्री श्रीवास्तव वर्ष 1988 अगस्त से मप्र. विद्युत मंडल की सेवा में बतौर स्नातक प्रशिक्षु पीजीटीआई कोरबा पूर्व में नियुक्त किए गए। वर्ष 1989 में सहायक अभियंता के तौर पर उनकी पहली पदस्थापना हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पश्चिम में कार्यालय-अधीक्षण अभियंता (संचालन डिविजन क्रं-दो) में की गई, जहां वे दिसंबर वर्ष 1996 तक कार्य करते रहे। इसके बाद उनकी विद्युत संयंत्र में अंतरविभागीय नियुक्ति 210 मेगावॉट की इकाई क्रमांक-दो में हुई, यहां उन्होंने टरबाईन मेंटेनेंस में कार्य किया। वर्ष 2007 में श्री श्रीवास्तव को कार्यपालन अभियंता के पद पर पदोन्नति मिलने के बाद वृत्त कार्यालय-संचालन-दो में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री श्रीवास्तव बताते है कि वर्ष 2011 में 210 मेगावॉट की इकाई क्र.-03 में टरबाईन आयल का तापक्रम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उन्होंने समय पर फाल्ट ढूंढ़कर विद्युत इकाई को ट्रिप होने से बचाया। इन उपलब्धियों के लिए उन्हें विशेष पुरस्कार के साथ मुख्यालय स्तर पर सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। श्री श्रीवास्तव ने वर्ष 2007 से वर्ष 2018 तक बतौर कार्यपालन अभियंता 210 मेगावॉट इकाई के टरबाईन मेंटेनेंस डिविजन-दो और 500 मेगावॉट विस्तार परियोजना में टरबाईन मेंटेनेंस के दायित्वों को बखूबी निभाया। इस दौरान कई बार विशेष कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया।

वर्ष 2018 में वे अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नत हुए। इस दौरान श्री श्रीवास्तव 500 मेगावॉट विस्तार परियोजना के टरबाईन मेंटेनेंस की जिम्मेदारी निभाते रहे । वर्ष 2023 में अति. मुख्य. अभियंता के पद पर पदोन्नति मिलने उपरांत अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र, मड़वा में पदस्थ किए गए। वर्ष 2024 में उन्हें मुख्य अभियंता के रूप में पदोन्नति दी गई और उन्हें हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम में पदस्थ किया गया। यहां पर श्री श्रीवास्तव बेहतर टीम वर्क के साथ विद्युत संयंत्रों के कुशल संचालन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

वे विद्युत मंडल एवं पॉवर कंपनी की 37 वर्ष की लंबी सेवा अवधि में करीब 24 वर्ष टरबाईन मेंटेनेंस के कार्यों में सलग्न रहें जिसका उन्हें दीर्घ अनुभव है। कोरबा पश्चिम में 210 मेगावॉट और 500 मेगावॉट विस्तार परियोजना के टरबाईन मेंटेनेंस में कार्य करना श्री प्रवीण श्रीवास्तव के लिए गौरवशाली और अद्भुत अनुभव रहा है।

श्री श्रीवास्तव की रूचि संगीत एवं खेल में हैं। इसके अलावा वह मंच संचालन के लिए काफी मशहूर हैं। वे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के समारोह का संचालन सफलतापूर्वक करते रहे हैं।श्री श्रीवास्तव अभियंता संघ के केंद्रीय स्तर के पदाधिकारी रहे हैं और उन्होंने कई बड़े कार्यक्रमों का मंच संचालन किया है। श्री श्रीवास्तव की धर्मपत्नी श्रीमती रूबी श्रीवास्तव गृहिणी हैं। वह समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं। वह संकल्प महिला मंडल की कार्यकारिणी में सक्रिय पदाधिकारी रहीं हैं। अभी वह संकल्प महिला मंडल की अध्यक्षा हैं। उनकी रूचि ड्राइंग एवं पेंटिंग में है। उनकी पुत्री अदिति ने निरमा, अहमदाबाद से बी.टेक. और सिम्बियोसिस पुणे से एमबीए. किया है। उनके दामाद श्री गौरव भी बी.टेक. और एमबीए. हैं। अभी दोनों ही बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत है।

श्री श्रीवास्तव हमेशा अपने कनिष्ठ साथियों के साथ अपना ज्ञान और अनुभव साझा करते हैं। वह उनके साथ कार्य करने वाले अभियंताओं को भी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में सदैव तत्पर रहे हैं। श्री श्रीवास्तव कार्यक्षेत्र में टीम भावना के साथ परस्पर सहयोग को महत्व देते है।

इस स्तंभ में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के वरिष्ठ अधिकारियों, विभाग प्रमुखों के जीवन वृत्त का प्रकाशन क्रमिक रूप से किया जा रहा है ताकि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से तीनों पॉवर कंपनियों के प्रदेश भर में पदस्थ अधिकारी तथा कर्मचारी प्रेरणा लें। अपने-अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठतम कार्य निष्पादन के लिये न सिर्फ नियमित दायित्वों का निर्वाह श्रेष्ठता से करें बल्कि नवाचार से प्रचलित परिपाटियों में बेहतर सकारात्मक सुधार के माध्यम भी बनें।

▪ **संपादक**



बिजली की कहानी 5

उमेश कुमार मिश्र
अतिरिक्त महाप्रबंधक, जनसंपर्क
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज

रोमांचक शुरूआत - छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का गठन लगभग असंभव से संभव होने वाली एक रोमांचक दास्तान की तरह है। राज्य गठन के समय अविभाजित मध्यप्रदेश के पश्चिमी हिस्से में, कोरबा में स्थापित बिजलीघरों से ज्यादातर बिजली आपूर्ति होती थी। मध्यप्रदेश में इस बात को लेकर चिंता हो गई थी कि यदि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अलग हो गया तो मध्यप्रदेश में अनायास ही बिजली का अभाव हो जाएगा। इस परिस्थिति में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में पहले ही यह व्यवस्था कर ली गई थी कि राज्य विभाजन होने के बावजूद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का गठन न किया जाए। मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम केंद्रीय कानून था अतः इसके विरुद्ध जाकर छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल का गठन बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था।

छत्तीसगढ़ विद्युत अभियंता संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे श्री पीएन सिंह बताते हैं कि मुख्यमंत्री श्री जोगी को यह कदम उठाने के लिए तैयार करने में अभियंता संघ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस वक्त रायपुर में पदस्थ विद्युत मण्डल के वरिष्ठ अधिकारी श्री एएमके भरोस के नेतृत्व में श्री सिंह सहित अभियंता संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी से चर्चा की और उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के गठन के सकारात्मक पहलुओं से अवगत कराया। प्रारंभिक दौर में श्री जोगी केंद्रीय कानून के खिलाफ जाने में सहमत नहीं थे लेकिन जब उन्हें यह बताया गया कि यह एक कदम नवगठित राज्य के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा तो श्री जोगी ने इसे किसी भी हालत में यह कार्य पूरा करने का दायित्व सौंपा।

मध्यप्रदेश को हो रही अंधाधुंध बिजली आपूर्ति बंद होने से एक ओर जहां छत्तीसगढ़ में तत्काल प्रभाव से विद्युत कटौती बंद हो गई और इसके सरप्लस ऊर्जा राज्य बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

पारेषण तंत्र का क्रमिक विकास

अविभाजित मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के जमाने में छत्तीसगढ़ की धरती का अति उच्चदाब क्षमता का पहला उपकेन्द्र सन् 1958 में भिलाई में स्थापित हुआ। 132 केवी क्षमता का दूसरा उपकेन्द्र वर्ष 1959 में बिलासपुर में तथा इसी क्षमता का तीसरा उपकेन्द्र वर्ष 1967 में भिलाई में स्थापित हुआ। वर्ष 2000 तक अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय तक 132 केवी उपकेन्द्रों की संख्या बढ़कर 20 हो गई।

जहां तक 220 केवी और 400 केवी उपकेन्द्रों का सवाल है तो यह जानना दिलचस्प होगा कि तीनों बड़ी क्षमताओं के प्रथम विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना भिलाई जिला दुर्ग में ही हुई। इसका प्रमुख कारण उस समय बिजली की सर्वाधिक मांग भिलाई इस्पात संयंत्र तथा इसके आसपास स्थापित सहायक उद्योगों में ही थी। यह जानना



डॉ. सुशील त्रिवेदी
(आईएएस)
पूर्व सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

मध्यप्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य गठन के लिए भारत सरकार ने जो अधिनियम संसद से पारित कराया था उसमें यह विशिष्ट प्रावधान था कि प्रारंभिक वर्षों में छत्तीसगढ़ में उत्पादित होने वाली बिजली का उपयोग छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश दोनों एक निर्धारित अनुपात में करेंगे। इस अनुपात का निर्धारण केंद्र द्वारा किया गया था जो अधिकतर मध्यप्रदेश के हित में था। छत्तीसगढ़ राज्य बना तो हालत यह थी कि मंत्रालय, राजभवन और मुख्यमंत्री आवास को भी लगभग हर दिन बिजली कटौती का सामना करना पड़ता था। ऐसे में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी ने आनन-फानन में यह निर्णय लिया कि किसी भी हालत में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का गठन होगा। उन्होंने तत्कालीन मुख्य सचिव श्री अरूण कुमार को इस बाबत् कार्यवाही करने का निर्देश दिया। यह कार्य केंद्रीय कानून के विरूद्ध था अतः स्वाभाविक रूप से उन अर्थों में अवैध था अतः श्री अरूण कुमार ने अपने तये इस कार्य में हाथ डालने में असमर्थता जताई। मुख्यमंत्री के सचिव श्री सुनिल कुमार ने दिमागी घोड़े दौड़ाये और यह रास्ता निकाला गया कि यह कार्य अधिकारियों के स्तर पर न होकर सीधे सरकार के स्तर पर और सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति की तरह किया हुआ दिखना चाहिए। इस तरह अंततः नवंबर 2000 के दूसरे सप्ताह में ही मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर श्री जोगी ने यह निर्देश दिया कि छत्तीसगढ़ के लिए अलग से विद्युत मंडल गठन करने और यहां उत्पादित बिजली का उपयोग यहीं करने के लिए एक अधिसूचना जारी कर दी जाए। वैध-अवैध की जो भी स्थिति बनेगी ,सरकार के मुखिया होने के नाते इसकी जिम्मेदारी वे स्वयं लेंगे और अधिकारियों पर कोई आंच नहीं आने देंगे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह निर्देश इतनी कड़ाई से दिए कि इस बाबत् एकपक्षीय अधिसूचना 15 नवंबर 2000 को जारी कर दी गई। इसके साथ ही राज्य में तत्काल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अस्तित्व में आने का मार्ग प्रशस्त हो गया। मध्यप्रदेश में तात्कालिक असर पड़ना स्वाभाविक था। मध्यप्रदेश के शहरों और गांवों में बिजली कटौती शुरू हुई और उद्योगों को भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।एक तरह से हाहाकार मच गया। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के बीच राजनीतिक और प्रशासनिक तनाव बढ़ गया। उधर केन्द्र शासन के पास भी आपत्ति दर्ज कराई गई। बहरहाल, जो होना था सो हो गया। दिल्ली में बैठक तय हुई, उसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमने-सामने बैठाकर बात की गई। श्री जोगी ने अपना निर्णय वापस लेने से मना किया तो बात समझौते की आई। आखिर यह तय हुआ कि छत्तीसगढ़ की सरप्लस बिजली पर मध्यप्रदेश का पहला अधिकार होगा लेकिन वह खरीदी गई बिजली के लिए तत्काल और नकद भुगतान मध्यप्रदेश करेगा। मजबूरीवश मध्यप्रदेश को यह शर्त माननी पड़ी । बहरहाल, छत्तीसगढ़ को ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में उठा यह पहला कदम गैर कानूनी जरूर था लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सिद्ध हुआ।





प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी के कार्यकाल के अंतिम दिनों में शिलान्यास, द्वितीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रथम कार्यकाल में परियोजना का कार्य पूर्ण करते हुए नये बिजली घर का लोकार्पण। डॉ. रमन सिंह के तीनों कार्यकालों में प्रदेश में विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण परियोजनाओं में अभूतपूर्व तथा ऐतिहासिक वृद्धि का कीर्तिमान...

भी दिलचस्प होगा कि प्रदेश के पहले बिजलीघर कोरबा से बिलासपुर होते हुए रायपुर और भिलाई की ओर बिजली प्रवाह का क्रम नहीं था बल्कि इसके उल्टे भिलाई में आने के पश्चात ही बिजली का ट्रांसमिशन रायपुर से बिलासपुर की ओर हुआ।

इस क्रम में यह उल्लेख करना उचित होगा कि जिस तरह 132 केवी का पहला उपकेन्द्र वर्ष 1958 में भिलाई में स्थापित हुआ उसी तरह 220 केवी क्षमता का पहला उपकेन्द्र भी भिलाई में वर्ष 1967 में और 400 केवी क्षमता पहला उपकेन्द्र भी खेदामारा (भिलाई) में ही वर्ष 1983 में स्थापित हुआ। सुलभ संदर्भ के लिए विभिन्न उपकेन्द्रों के स्थापना वर्षवार सूची प्रस्तुत है।

132 केवी उपकेन्द्र-

भिलाई (1958), बिलासपुर (1959), भिलाई (1967), किरंदुल (1968), रायगढ़ (1969), दल्ली राजहरा (1975), गुढ़ियारी (1976), महासमुंद (1976), चांपा (1977), विश्रामपुर (1977), जगदलपुर (1979), सिमगा (1980), दर्री (1981), राजनांदगांव (1982), बिरगांव (1983), धमतरी (1984), मनेंद्रगढ़ (1992), बलौदाबाजार (1996), पत्थलगांव (1996), रूआबांधा (2000), अंबिकापुर (2004), सारंगढ़(2001), कवर्धा (2002), कचना (2002), कांकेर (2002), डोंगरगढ़ (2002), सक्ती (2003), राजिम (2003), बैकुंठपुर (2006), अकलतरा (2003), मुंगेली (2003), धमधा (2004), कुरूद (धमतरी) (2005), गुण्डरदेही (2005), बरमकेला (2006), नवागढ़ (2006), घरघोड़ा (2006), साजा (2009), तुलसी(2006), जशपुर (2006), डोंगरगांव (2007), झलप (2009), कुरूद (भिलाई)(2008), सिलपहरी (2008), खरसिया (2008), बागबहरा (2009), चकरभाठा (2011), बालोद (2010), पंडरिया (2010), माना (2010), भानुप्रतापपुर (2011), मंदिर हसौद (2012), कुहेरा (2012), उरला (2012), रसमड़ा (2012), बलरामपुर (2013), मगरलोड (2013), सरोना (रायपुर) (2013), सांकरा (2013), गंडई(2013), कोण्डागांव (2013), विश्रामपुर (2013), प्रतापपुर (2014), रतनपुर (2014), पथरिया (2014), गरियाबंद (2014), पुलगांव (दुर्ग) (2014), जैजैपुर (2015), कसडोल (2015), रेंकी (2016), कोनी (2016), रावणभाठा (2016), जगदलपुर (2017), चारामा (2018), सुकमा (2018), तखतपुर (2018), कोंडातराई (2018), डभरा (2018), मोहला (2018), बसना (2018), शिवरीनारायण (2018), भखारा (2018), लोरमी (2018), कोरबा (2003-04), बेरला (2018), बोरझरा (2007), बटोली (2018), कांसाबेल (2018), राजपुर (2018), वाड्रफ नगर (2018), नगरी (2018), पखांजूर (2018), दोरनापाल (2018), छुरी खुर्द (2018), नारायणपुर (2019), धरदेही (2019), बीजापुर (2020), उदयपुर (2021), खैरागढ़ (2022), इंदामारा (2022), खरमोरा (2022), इंदागांव (2023), मठखरोरा (2023), सिलतरा फेस-2 (2023), अमलेश्वर (2023), छावनी (2023), गुल्लू (आरंग) (2024), बैजलपुर (2024), टेमरी (बेमेतरा) (2024), मस्तूरी (बिलासपुर) (2025)। इनमें से कुछ उपकेन्द्रों का उन्नयन कालांतर में 220 केवी उपकेन्द्र के रूप में हुआ।

220 केवी उपकेन्द्र-

दुर्ग (1967), बारसूर (1980), भाटापारा 1984, उरला (1989), रायगढ़ (1997), मोपका (2002), सरायपाली (2014), कोटमीकला (2003), गुरूर (2004), सिलतरा (2006), बेमेतरा (2007), बनारी, (चांपा) (2007), महासमुंद (पारसवाणी) (2007), सुहेला (2008), राजनांदगांव (ठेलकाडीह) (2009), डोमा (रायपुर) (2010), पाटन (2024), रायता (रायपुर) (2013), विश्रामपुर (2013), छुरी (2014), मुंगेली (2014), गेरवानी (2016), जगदलपुर (2017), कवर्धा (2018), बोरझरा (2018), कुथरेल (धरसीवा) (2018), नारायणपुर (2019), धरदेही (2019), कुरूद (धमतरी) (2020), कोरबा (2021). इनमें से कुछ उपकेन्द्रों का उन्नयन कालांतर में 400 केवी उपकेन्द्र के रूप में हुआ।

400 केवी उपकेन्द्र-

खेदामारा (1983), रायता (रायपुर) (2013), जगदलपुर (2017), कुरूद (धमतरी) (2020).

इस तरह वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 400/220 केवी क्षमता के उपकेन्द्रों की संख्या 4 है तथा ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता 3465 एमवीए है। 220/132 केवी क्षमता के उपकेन्द्रों की संख्या 28 है तथा ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता 10960 एमवीए है। 132/33 केवी क्षमता के उपकेन्द्रों की संख्या 103 है तथा ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता 12089.50 एमवीए है। इस प्रकार कुल अति उच्चदाब उपकेन्द्रों की संख्या 135 तथा ट्रांसफॉर्मरों की कुल क्षमता 26514.50 एमवीए है।

विश्व पर्यावरण दिवस पर विविध आयोजन

कोरबा पूर्व में ...



डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व में कार्यपालक निदेशक (पीजीटीआई) श्री एस.के. बंजारा, मुख्य अभियंता (उत्पा.) श्री संजीव कंसल, प्रेरणा महिला मण्डल की अध्यक्षा श्रीमती निवेदिता बंजारा, श्रीमती अल्का कंसल एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं राजेश्वरी रावत, श्री सुनील सरना, श्री राजा बाबू कोसारे, श्री एल.एन. सूर्यवंशी, व्ही. श्रीमती के. सेन चौधरी एवं वरि. मुख्य रसायनज्ञ श्रीमती मालती जोशी, मुख्य रसायनज्ञ- श्री गोवर्धन सिदार, श्री जितेन्द्र सिंह, अधीक्षण अभियंताओं- सर्वश्री एच.एल. भुआर्या, आर.पी. टण्डन, श्री आलोक सक्सेना, वरिष्ठ रसायनज्ञ- श्री शैलेन्द्र शुक्ला द्वारा वृक्षारोपण किया गया। प्लास्टिक थैली के उपयोग बंद करने एवं जूट की थैलियों का इस्तमाल को बढ़ावा देने जूट की थैलियों का भी वितरण किया गया।

कोरबा पश्चिम में ...

हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पश्चिम में विश्व पर्यावरण दिवस मुख्य अभियंता श्री प्रवीण श्रीवास्तव ने ''एक पेड़ मां के नाम'' अभियान के अंतर्गत फलदार पौधों का रोपण किया। उन्होंने कहा कि पौधे को लगाने के साथ ही उन्हें पेड़ बनने तक बचाए रखना भी हमारा नैतिक कर्तव्य है।

परियोजना प्रबंधक श्री बीपी पाटले, अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री एमके गुप्ता, श्री पीके स्वैन, श्री राजेश पांडेय, श्री पीके मलघानी, श्री केएनबी. राव, श्री सुधीर पंड्या, श्री एससी पाठक और वरिष्ठ मुख्य रसायनज्ञ श्री एके. कुरनाल एवं संकल्प महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती रूबी श्रीवास्तव सहित महिला मंडल की पदाधिकारियों द्वारा भी अपने हाथों से पौधे रोपे गए।

निबंध लेखन प्रतियोगिता में श्रीमती राधा पैगवार, श्रीमती डॉ. मंजुला साहू, श्रीमती डॉ. श्वेताम्बरी महंता, श्रीमती भावना धुर्वे ने, चित्रकला स्पर्धा में छात्र-छात्राएं रियांशी ठाकुर, अभिजीत साहू, अयांश पटेल, कारून्या पटेल, समिता बघेल, कृतिका कंवर, सुनिधि मिश्रा, देविशा कर, शौर्य साहू, नारा स्पर्धा में श्री मनोज कुमार पटेल, श्री श्रीराम साहू, श्रीमती राधा पैगवार एवं श्री परदेशी लाल चंद्रा, श्री कार्तिक दास महंत, मीना कैवर्त्य को पुरस्कार दिया गया।



मड़वा में ...

अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा में विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्य अभियंता श्री एचएन. कोसरिया एवं अतिथियों द्वारा पौधे लगाए गए।



विशिष्ट अतिथि पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर के मुख्य रसायनज्ञ श्री सूरज कुमार धुर्वे, अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री एके शाह, श्री आरएल ध्रुव, श्री आरके साव और श्री एन. लकरा एवं आकृति महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती शशि कोसरिया समेत महिला मंडल की पदाधिकारियों ने पौधे रोपे।

स्पर्धा के विजयी प्रतिभागियों को मुख्य अभियंता श्री एचएन. कोसरिया एवं अतिथियों के हाथों पुरस्कृत किया गया। नारा स्पर्धा में डॉ. विकेंद्र सिंह, श्री अभिजीत मालवंकर, श्री सतीश यदु, कविता स्पर्धा में डॉ. श्री विकेंद्र सिंह, श्री हर्षवर्धन श्रीवास, श्री ब्रजेश अग्रवाल, निबंध स्पर्धा में श्री संजीव कुमार सारथी, श्री मनमोहन चंद्रा और श्री जितेंद्र जायसवाल, चित्रकला में आद्या चंद्रा, अनाया लकरा, इशान्या मांडले, तनीशा साहू, गौरांगी चंद्रा, भाव्या नेताम और संस्कार झा को पुरस्कृत किया गया। आवासीय परिसर में हुई स्पर्धाओं में श्रीमती अंकिता वर्मा, श्रीमती रूचि देवांगन, श्रीमती ममता सिंह, श्रीमती रूचिका साहू, श्रीमती श्वेता परप्यानी और श्रीमती तरणि साहू को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रबंधक (पर्यावरण) श्री संजय झा द्वारा किया गया।

रायपुर में ...

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पॉवर कंपनी मुख्यालय स्थित वितरण कंपनी के केन्द्रीय लेखा इकाई द्वारा कार्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

विभिन्न प्रकार के छायादार व औषधीय पौधे लगाए गए। कर्मचारियों ने ''एक पौधा, एक जीवन-मिलकर करें पर्यावरण संरक्षण।'' के नारे लगाए। उपस्थित कर्मियों को पौधे भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में सहायक प्रबंधक श्री चंद्रशेखर शिंदे, श्रीमती किरण शुक्ला, श्री प्रणेश देवांगन,श्री मुकेश पैकरा समेत अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।





POWER SECTOR ROUND UP 7

Vinay Pandey
S.E. CSPGCL
Raipur

Break Through

AERB has granted approval for four 700MWe units at Mahi Banswara in Rajasthan, by Anushakti Vidyut Nigam, a JV between NPCIL & NTPC. The project is part of "fleet mode approach" by GOI for 10 PHWR (Pressurized Heavy Water Reactor) units.

China's Linglong-1, the World's first land based commercial mini nuclear reactor (also called nuclear power bank) of 125 MW capacity, is now in the final installation phase.

Policy

Gas Based Stations (GBS) exhibit another policy contradictions. While MoP recently issued directed min 50% dispatch in June and government declared goal to more than double the share of gas in energy mix by 2030. In FY 24-25, all India avg PUF for GBS was 14.5% (7 GW in SR < 4%).

In another policy turmoil, while long term PPA for Thermal power are making a come back and mega thermal projects are being launched, during day time RTM power prices are nose diving. On 25th May, RTM prices hit near zero.

As per reports, with target of 10 GW SHP in a decade, GoI is planning to provide 30% support to developers. Current capacity is 5 GW while potential is 21 GW.

On 10th June, to make ESS investor friendly, MoP proposed key amendments to Electricity Rules 2005. Now the ESS may be installed either as standalone system or as part of power generation / distribution/ transmission system.

Legal / Regulatory

After a decade long dispute with SEBI, on 22nd May, CERC issued the "Draft Guidelines for Virtual Power Purchase Agreement (VPPA)" providing crucial regulatory clarity.

Commercial

On 19 May, Reliance Power signed a 50-50 JV with Bhutan's DHI to setup Bhutan's largest solar power plant 500 MW electricity with cost upto 2000 Cr.

With 22% jump in net profit for FY 24-25, over next three years NTPC plans to increase standalone capex to around Rs 32000 Cr annually. FY 24-25 standalone Capex was 22965 Cr (YoY 18% higher) and group Capex was 44636 (up by 13%).

In response to NPCIL's RFP for 220 MWe BSRs as captive units, several Indian companies including BSNL, Indian Railways, Reliance, Adani, Tata Power and many others have expressed interest

New Development

Consequent to SEBI's agreement with CERC, in a filing dated 06th June, MCX announced regulatory approval to launch electricity derivatives, which will allow power generators, distribution companies and large consumers to hedge against price volatility and manage price risks more effectively.

While in UP private companies are bidding for State Discom, in Maharashtra, govt owned Mahavitaran is set to challange private Discoms. MSEDCL, one of the largest Discoms in India (457 cities, over 41,928 villages, 3Cr + consumers & 26000 MW supply) has applied to MERC for a parallel license for key Mumbai regions.

Statistical

As per NLDC data, in May, India's peak power demand touched a record high of 2,30,993 megawatts (MW) and energy supply met was 148718 MU. During the month IEX logged 10,946 MU with REC YoY trade up by 65%. With unseasonal rains and early monsoon, the average DAM MCP dropped by 22% to Rs 4.12 / unit and RTM dropped by 28% Rs 3.43 / Unit.

Achievements

India added 6.7 GW of solar capacity in Q1 of 25. Though it's 54% of total additions but in solar is 25% YoY lower. Large scale projects contributed 82% while rooftop share was 18%.



श्री हरिनंदन मंडल, श्री राजेंद्र कुमार तिवारी, श्री श्याम लाल निषाद, श्री राजेश कुमार चिंदेकर, श्री राजेंद्र प्रसाद पाण्डेय, श्री नेहरू बेहरा, श्री चौतराम नाग - छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के भारप्रेषण केंद्र के सभा में 30 मई को 7 कर्मचारियों को विदाई दी गई। पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री राजेश कुमार शुक्ला ने सेवानिवृत्तजनों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृतिचिन्ह भेंट कर सुखमय जीवन की कामना की। कार्यपालक निदेशक श्री के.एस.मनोठिया, श्री एमएस चौहान, श्रीमती ज्योति नंनौरे, श्री वीके दीक्षित, मुख्य अभियंता श्रीमती शारदा सोनवानी, श्री ए.एम. परियल एवं श्री संजय तिवारी आदि भी उपस्थित थे। संचालन प्रकाशन अधिकारी श्री गोविंद पटेल ने किया।



श्री दिलीप कुमार सैनी, श्री दिलीप कुमार अग्रवाल, श्री मनोज कुमार वर्मा, श्री के.सन्यासी राव, श्री जवाहर लाल पंद्रे, श्री मोहम्मद शफीक, श्री अमृतलाल मन्नेवार, श्री यदुनंदन प्रसाद वर्मा, श्री सुखराम कौशिक - लोड डिस्पैच सेंटर से 30 अप्रैल को 9 विद्युतकर्मी सेवानिवृत्त हुए । इस अवसर पर कार्यपालक निदेशकगण श्री के.एस.मनोठिया तथा श्री संजय पटेल ने सेवानिवृत्तजनों को प्रशस्ति पत्र, स्मृतिचिन्ह आदि भेंट किया। इस अवसर पर के.बी.पात्रे, श्रीमती शारदा सोनवानी, श्री अजय सिंह, श्री आर.के.तिवारी आदि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री उमेश कुमार मिश्रा, अतिरिक्त महाप्रबंधक ने किया। श्री दिलीप कुमार अग्रवाल तथा मनोज वर्मा का अभिनंदन मुख्य अभियंता (एच.आर.- ट्रांसमिशन) श्री ए.एम.परियल तथा अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री विनोद अग्रवाल ने किया।



श्री आनंद राम चंद्रा एवं श्री मोहन लाल ठाकुर - डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व से माह मई में श्री आनंद राम चंद्रा एवं श्री मोहन लाल ठाकुर को मुख्य अभियंता संजीव कंसल ने पुष्पगुच्छ, प्रशस्ति पत्र एवं कलाई घड़ी, से सम्मानित कर विदाई दी। अति. मुख्य अभियंता -श्रीमती राजेश्वरी रावत, श्री सुनील सरना, एवं वरि. मुख्य रसायनज्ञ श्रीमती मालती जोशी उपस्थित थी। संचालन श्री पन्ना लाल साहू एवं अभार प्रदर्शन श्री आर.पी. टण्डन द्वारा किया गया।



श्री राजेश कुमार - पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मानव संसाधन विभाग में पदस्थ प्रबंधक श्री राजेश कुमार को 30 मई को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक (मा.सं) श्री सतीश कुमार गजपाल ने श्री कुमार को बधाई देते हुए उनको स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में उपमहाप्रबंधक श्री राजेश श्रीवास्तव, श्रीमती मल्लिका बेक,श्रीमती नम्रता राठौर समेत अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे।



श्री आर.के.अरोरा, श्री ईश्वर प्रसाद चन्द्रा, श्री बंशी दास मानिकपुरी - बिलासपुर क्षेत्र से माह अप्रैल में 03 अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त होने वाले में श्री आर.के.अरोरा, अधीक्षण अभियंता, श्री ईश्वर प्रसाद चन्द्रा, मुख्य सुरक्षा सैनिक, श्री बंशी दास मानिकपुरी लाइन सहायक श्रेणी-एक को कार्यपालक निदेशक श्री ए.के. अम्बस्ट ने विदाई दी।इस अवसर पर अति.मुख्य अभियंता श्री डी.के.भोजक, अधीक्षण अभियंता श्री सुरेश जांगड़े, कार्यपालन अभियंता श्री बी.के. सरकार एवं कार्यालय के समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।



श्री अनुप कुमार मिश्रा, श्री दामोदर प्रसाद साहू, श्री जनीराम कर्ष, श्री महेश कुमार सिंह, श्री चिंताराम कैवर्त एवं एएनएम. श्रीमती बानी बिश्वास - हसदेव ताप विद्युत गृह (एचटीपीएस) कोरबा पश्चिम से अप्रैल माह में कार्यपालन अभियंता श्री अनुप कुमार मिश्रा, वरिष्ठ पर्यवेक्षक श्री दामोदर प्रसाद साहू, कनिष्ठ पर्यवेक्षक श्री जनीराम कर्ष, श्री महेश कुमार सिंह, श्री चिंताराम कैवर्त एवं एएनएम. श्रीमती बानी बिश्वास सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर मुख्य अभियंता श्री पीके श्रीवास्तव ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति चिह्न व सेवा प्रमाण-पत्र भेंट किया । इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता सर्वश्री एमके गुप्ता, पीके स्वैन और केएनबी राव उपस्थित थे।



श्री शिवप्रसाद, श्री दिलहरण लाल, श्री ललित मोहन नायक, श्री लक्ष्मी कुमार चंद्रा, श्री समेलाल गोड़, श्री बड़वंत राव, श्री गुरूचरण चंद्रा, श्री शिव कुमार साहू, श्री लोकनाथ चंद्रा, श्री जगत राम राठौर और कक्षसेविका लक्ष्मी बाई यादव - एचटीपीएस कोरबा पश्चिम से मई में सेवानिवृत्त कर्मियों को मुख्य अभियंता पीके श्रीवास्तव ने स्मृतिचिन्ह व सेवा प्रमाण-पत्र भेंट किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री एमके गुप्ता, श्री पीके स्वैन और श्री एससी पाठक उपस्थित थे।

गोपनीय प्रतिवेदन लिखने के निर्देश - वर्ष 2024 में संशोधित

1. गोपनीय रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह एक अधिकारी के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके करियर में आगे की उन्नति के लिए बुनियादी और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। जिस अधिकारी की रिपोर्ट लिखी जा रही है। रिपोर्ट करने वाले, समीक्षा करने वाले और स्वीकार करने वाले अधिकारी को जिम्मेदारी की भावना के साथ प्रारूप को भरना चाहिए।
2. गोपनीय रिपोर्ट के माध्यम से निष्पादन मूल्यांकन का उपयोग मानव संसाधन विकास हेतु सहायक के रूप में किया जाना चाहिए। रिपोर्टिंग अधिकारी को यह महसूस होना चाहिए कि गोपनीय रिपोर्ट का उद्देश्य एक अधिकारी का विकास करना है ताकि वह अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास कर सके। रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी और समीक्षा करने वाले अधिकारी को जिस अधिकारी की रिपोर्ट लिखी जा रही है उसके प्रदर्शन, दृष्टिकोण या समग्र व्यक्तित्व का सूक्ष्मतापूर्वक विश्लेषन करना चाहिए।
3. कॉलमों को उचित ढंग से. सावधानीपूर्वक एवं ध्यान से पर्याप्त समय देकर भरा जाना चाहिए।
4. प्रत्येक उत्तर वर्णनात्मक रूप में दिया जाना चाहिए। शब्दों और वाक्यांशों को ध्यान से चुना जाना चाहिए और प्राधिकारी के इरादे को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करना चाहिए। कृपया स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग करें। साथ ही किसी भी विशेषता पर अपनी टिप्पणी देते समय "उत्कृष्ट" "बहुत अच्छा" "अच्छा" "औसत" या "औसत से कम" जैसे शब्दों का उपयोग करें।
5 संबंधित दोनों अधिकारियों द्वारा लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए। लक्ष्यों को निर्धारित करते समय, कार्य की प्रकृति, क्षेत्र और विशेष सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए क्रमवार प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो अधिकारी के कार्य क्षेत्र की प्रकृति के लिए विशिष्ट हो सकती है।
6. यद्यपि कार्य निष्पादन मूल्यांकन एक वित्तीय वर्ष के अंत की कवायद है ताकि यह मानव संसाधन विकास के लिए एक उदाहरण बन सके, रिपोर्टिंग अधिकारी और जिस अधिकारी की रिपोर्ट की जा रही है. उन्हें प्रदर्शन की समीक्षा करने और आवश्यक सुधार करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान नियमित अंतराल में आपसी समन्वय के साथ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए।
7. प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता का यह प्रयास होना चाहिए कि वह अपने प्रदर्शन, आचरण, व्यवहार और क्षमता के संबंध में मूल्यांकक की यथासंभव सच्ची तस्वीर पेश करे।
8. मूल्यांकन केवल रिपोर्ट की अवधि के दौरान मूल्यांकनकर्ता के प्रदर्शन तक ही सीमित होना चाहिए।
9. समान स्तर (रैंक) के कुछ पद दूसरों की तुलना में अधिक कठिन हो सकते हैं। किसी भी पद में तनाव और तनाव की मात्रा समय-समय पर बहुत अधिक हो सकती है। मूल्यांकन के दौरान इन तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उचित रूप से टिप्पणी की जानी चाहिए।
10. सत्यनिष्ठा से संबंधित कॉलम को भरने में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए -
    (1) यदि अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदेह से परे है, इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।
    (2) यदि कोई संदेह हो तो उसे कॉलम में उल्लेख किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बारे में अलग से कारण बताते हुए टीप संलग्न की जाए।
11. रिपोर्टिंग और समीक्षा करने वाले अधिकारियों द्वारा समग्र ग्रेडिंग प्रदान की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि समग्र प्रदर्शन के आधार पर, रिपोर्टिंग अधिकारी मूल्यांकन को अच्छा यानी ग्रेड बी के रूप में ग्रेड करता है, तो उसे नीचे दिए गए अनुसार उसका उल्लेख करना चाहिए।

असाधारण / उत्कृष्ट (outstanding excellent)	A+
बहुत अच्छा (VERY GOOD)	A
अच्छा (GOOD)	B
औसत (Average)	C
औसत से कम (Below Average)	D

12. यदि मूल्यांकनकर्ता ने एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक अधिकारी के अधीन 120 दिनों से अधिक सेवा की है. तो वह अलग-अलग फॉर्म भरेगा और उन्हें संबंधित प्रस्तुत करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
13. (ए) मूल्यांकनकर्ता का अर्थ है- अधिकारी जिसका गोपनीय रिपोर्ट (सी आर) लिखा जाना है।
    (बी)रिपोर्टिंग अधिकारी का अर्थ है- जिसके Appraisee रिपोट करता है।
    (सी) समीक्षा अधिकारी का अर्थ है -रिपोर्टिंग अधिकारी के अगले उच्च अधिकारी।
    (डी) पदवार स्वीकार करने वाले प्राधिकारी (Accepting Authority) का विवरण निम्नानुसार है

क्र	पद	स्वीकार करने वाले प्राधिकारी
1	कनिष्ठ यंत्री	संबंधित अधीक्षण अभियंता

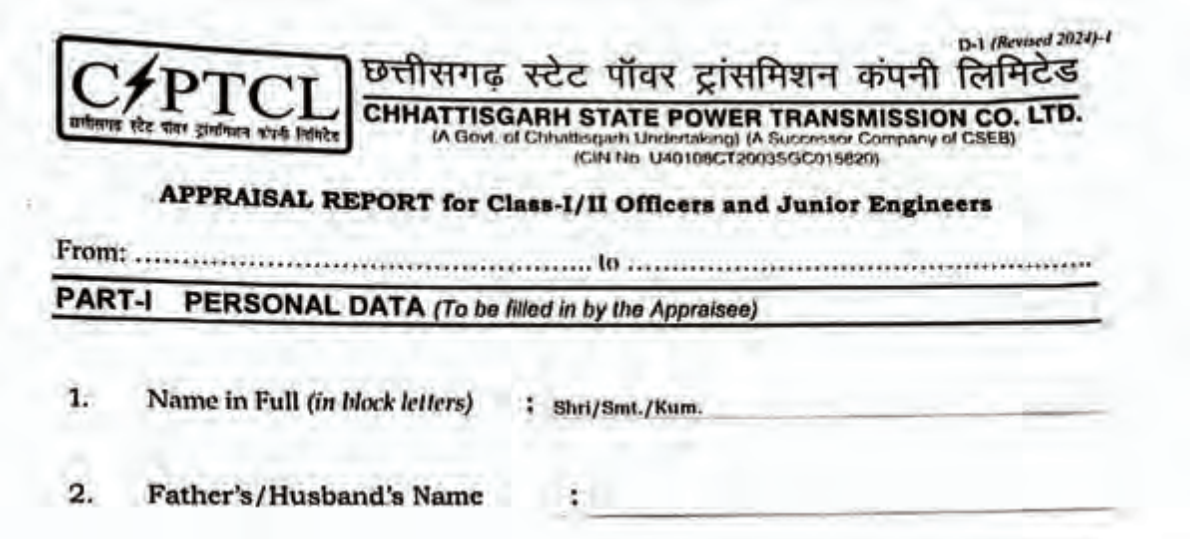

D-1 (Revised 2024)-I

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION CO. LTD.

(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking) (A Successor Company of CSEB)

(CIN No. U40108CT2003SGC015820)

APPRAISAL REPORT for Class-I/II Officers and Junior Engineers

From: ..... to .....

PART-I PERSONAL DATA *(To be filled in by the Appraisee)*

1. Name in Full *(in block letters)* : Shri/Smt./Kum. _____

2. Father's/Husband's Name : _____

2.	सहायक अभियंता (क्षेत्रीय एवं विद्युत गृह स्तर), सहायक अभियंता (मुख्यालय स्तर)	क्षेत्रीय/ विद्युत गृह प्रभारी मुख्य अभियंता, संबंधित कार्यालय प्रमुख मुख्य अभियंता
3	क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी	क्षेत्रीय/ विद्युत गृह प्रभारी मुख्य अभियंता
4	मुख्यालय में पदस्थ कल्याण अधिकारी	संबंधित कंपनी के मुख्य अभियंता(मा स)
5	कार्यपालन अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं समकक्ष	संबंधित कंपनी के प्रबंध निदेशक
6	वरिष्ठ कल्याण अधिकारी	मुख्य अभियंता मासंसाधन ट्रांसमिशन कंपनी
7	अति मुख्य अभियंता एवं उससे उच्च अधिकारी एवं समकक्ष अधिकारी	अध्यक्ष, पॉवर कंपनी

मुख्य अभियता अर्थात् यथासमय मुख्य अभियंता / कार्यपालक निदेशक

14. ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने परिपत्र कमांक 01-01 एआर/सीआर/ 238 दिनांक 02.02.2023 के माध्यम से गोपनीय रिपोर्ट गोपनीय चरित्रावली के सबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किये हैं, जिनका पालन संबंधित अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। उक्त परिपत्र के तहत स्व-मूल्यांकन प्रतिवेदक से स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी तक के विभिन्न स्तर के अधिकारियों को गोपनीय रिपोर्ट गोपनीय चरित्रावली पर कार्यवाही करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है, जो 10 जून से 10 अगस्त (अधिकतम) तक है। उपरोक्त निर्धारित समयावधि में गोपनीय रिपोर्ट / गोपनीय चरित्रावली प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी को रिपोर्टिंग अधिकारी समीक्षा अधिकारी स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र प्रेषित किये जावेंगे। अर्द्धशासकीय पत्र जारी किये जाने के उपरांत भी गोपनीय रिपोर्ट गोपनीय चरित्रावली प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अधिकारी के वेतन की 50 प्रतिशत राशि स्थगित रखने का प्रावधान किया गया है, जो उनके गोपनीय रिपोर्ट गोपनीय चरित्रावली संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत संबंधित लेखा इकाई द्वारा बहाल की जावेगी।

वार्षिक गोपनीय चरित्रावली (ACR) /मूल्यांकन प्रतिवेदन (AR) लिखे जाने हेतु पुनरीक्षित समय सीमा -

क्र (SN)	प्राधिकृत अधिकारी (NAME OF AUTHORITY)	उच्चाधिकारियों को वार्षिक गोपनीय चरित्रावली (ACR) / मूल्यांकन प्रतिवेदन (AR) भेजने की समय सीमा / Date by which Appraisal Report to be submitted to next higher authority		
		FOR ED /CE/ACE/SEs & equivalent ranks	FOR AE/EE & equivalent ranks	FOR class iii &IV staff
1	स्व मूल्यांकन प्रतिवेदक (appraisee)	10th June	10th June	-
2	प्रतिवेदन अधिकारी (reporting officer)	10th July	10th July	10th June
3	समीक्षक अधिकारी (reviewing officer)	10th Aug	10th Aug	10th July
4	स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी (accepting officer)	-	10th Sep	10th Aug

(स्त्रोत- मुख्य अभियंता कार्यालय, मानव संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा जारी सीआर प्रपत्र)

नया स्तंभ

चाहिए अदद तस्वीरें

जो बयां करती हैं अपने वक्त की कहानियां

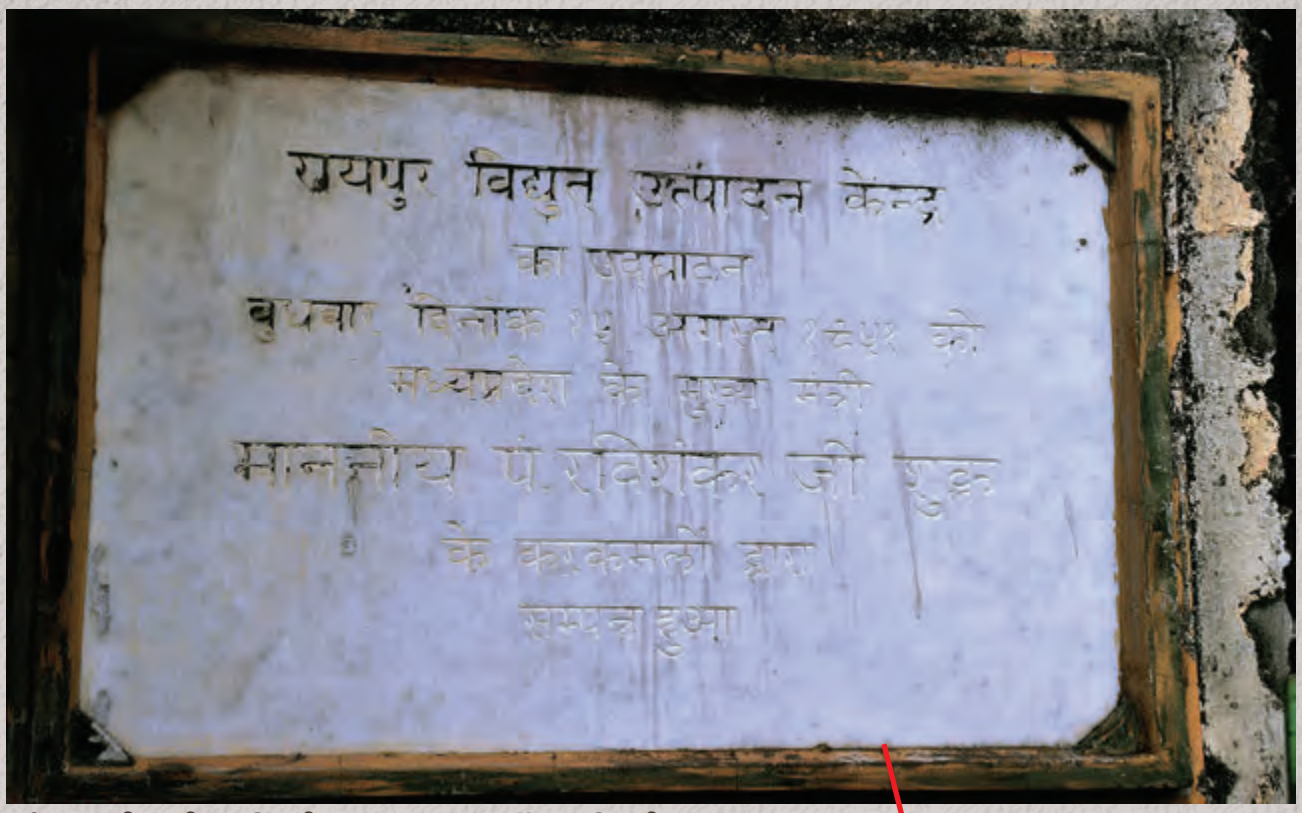

वर्ष 1951 की तस्वीर, गुढ़ियारी, रायपुर में 4 मेगावॉट का बिजली घर, विस्तृत कहानी संकल्प के अक्टूबर 2024 के अंक में

"एक तस्वीर हजार शब्द" यह कोरी कहावत नहीं बल्कि सच्चाई है। एक तस्वीर अपने वक्त की कहानी बयां करती है। अपने वर्तमान स्वरूप में छत्तीसगढ़ राज्य भले ही नवम्बर 2000 में बना हो लेकिन यहां बिजली की दस्तक तो 1915 के आसपास सुनाई देने लगी थी, फिर तो काल-क्रम के साथ विकास के कदमों के निशान बढ़ने लगे। बहुत सी पुरानी बातें, जिन दस्तावेजों में दर्ज होंगी वे इतने बिखरे हैं कि जैसे उपलब्ध नहीं हैं। जनश्रुतियों के साथ जनसहयोग से प्रदेश में बिजली के इतिहास के प्रमाणित दस्तावेज पुरानी तस्वीरों के माध्यम से जुटाने की जुगत है यह स्तंभ।

पाठकों से निवेदन है कि ऐतिहासिक महत्व की ऐसी तस्वीरें साझा करें, यहां प्रेषक के नाम और प्रेषित विवरण के साथ उन्हें प्रकाशित किया जाएगा।

– संपादक



पीएम सूर्य घर
मुफ़्त बिजली योजना

अतिशेष बिजली डिस्कॉम को बेच कर होगी **अतिरिक्त कमाई**



उपभोक्ता से बनें ऊर्जादाता



डबल सब्सिडी

मासिक बिजली बिल से कम पैसों में

केंद्र के साथ अब मिलेगी राज्य की भी सब्सिडी

लगाएं रूफटॉप सोलर प्लांट

1kW मात्र ₹15,000 में

2kW मात्र ₹30,000 में

आवेदन प्रक्रिया व अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर जाएं

https://pmsuryaghar.gov.in/

QR कोड स्कैन करें

सोलर प्लांट क्षमता	केंद्र सरकार की सब्सिडी	राज्य सरकार की सब्सिडी	कुल सहायता राशि	आसान मासिक EMI
1 kW	₹30,000	₹15,000	₹45,000	₹170
2 kW	₹60,000	₹30,000	₹90,000	₹341
3 kW	₹78,000	₹30,000	₹1,08,000	₹818

*बैंक द्वारा 6.5% ब्याज दर पर आसान किश्तों में 10 वर्षों के लिए ऋण सुविधा (ई.एम.आई.) उपलब्ध



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

हमारा संकल्प
हाफ बिजली से मुफ्त बिजली